● वर्ष-4
● अंक-107
रायपुर, शनिवार
14 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» स्वाद में कड़वा लेकिन गुणों की...

डबल इंजन की सरकार में मिल रहा डबल फायदा: नड्डा

जो रामराज्य के मूल्य हैं, वहीं हमारे लिए सुशासन के मूल्य - मुख्यमंत्री

रायपुर। देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से लोगों को डबल लाभ हो रहा है। आज भारत विश्व की पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगले पांच सालों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। केन्द्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कार्यक्रम में 1124 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

केन्द्रीय मंत्री नड्डा ने जनादेश परब में छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वप्रेरणा से लोकहित में पूरी जवाबदेही के साथ काम कर रही है। सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 18 लाख से अधिक जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई। मोदी की गारंटी के अनुरूप यहां किसानों से 3100 प्रति क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है। किसानों को उनके हक का 3716 करोड़ रूपए धान के बकाया दो साल के बोनस का भुगतान भी किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनादेश परब में घोषणा की कि अब से हर साल 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 'जनादेश परब' के रूप में मनाया जाएगा। आने वाले वर्ष में छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य निर्माता भारत रत्न अटलजी का यह शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की। श्री साय ने कहा कि अटलजी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश में सड़कों का जाल बिछाया। उसी से प्रेरणा लेकर हम अपने रजत जयंती वर्ष में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता में रखेंगे। उसके बाद के तीन वर्षों में भी हम अलग-अलग थीम पर काम करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जनादेश परब को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले साल किसान भाइयों के खाते में आपकी डबल इंजिन की सरकार ने 49 हजार करोड़ रुपए डाले हैं। हमने अपने शुरूआती तीन महीनों में ही प्राथमिकता के साथ महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की माताओं-बहनों को देना आरंभ किया। 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की अब तक 10 किश्तों में 6,530 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। पहली तारीख को हम यह राशि भेज देते हैं और जैसे ही माताओं-बहनों के खाते में राशि आती है उनका चेहरा गर्व से खिल जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जो रामराज्य के मूल्य हैं, वहीं हमारे लिए सुशासन के मूल्य हैं। हमने प्रशासन के हर स्तर पर सुशासन को सुनिश्चित किया है। हमने सुशासन के मूल्यों को सिस्टम में शामिल करने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया। सुशासन के लिए पारदर्शिता सबसे आवश्यक है और इसके लिए डिजिटल गवर्नेंस शुरू कराया है। लालफीताशाही को दूर करने हमने ई-आफिस प्रणाली आरंभ की है। इसमें डिजिटल माध्यम में नोटशीट आगे बढ़ती है। इससे समय-सीमा भी तय होती है और जवाबदेही भी तय हो जाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा के विकास के बगैर छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हमने वनोपज संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए काम किया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि हमने 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर साढ़े 5 हजार रुपए कर दी। जनजातीय गौरव दिवस के दिन हमने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा आदि को पांच-पांच हजार रुपए सम्मान निधि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण हम कर रहे हैं। कांगेर घाटी के गांव धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने दुनिया के 20 चुनिंदा गांवों में शामिल किया है। बस्तर और छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के मानचित्र में आ गए हैं। सरगुजा संभाग भी विश्व के पर्यटन नक्शे में स्थान बना रहा है। अभी-अभी जशपुर के मधेश्वर पहाड़ शिवलिंग को विश्व में सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला को हमने देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया है। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरगुजा और बस्तर में एयर कनेक्टिविटी आरंभ होने से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास के साथ ही यहां अब देश-विदेश से पर्यटकों के पहुंचने की राह खुल गई है। मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आगामी दो सालों में प्रदेश का सड़क नेटवर्क विकसित देशों की तरह हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सबसे बड़ी सफलता माओवादी मोर्चे पर मिली है। एक साल पहले किसी के लिए यह सोचना भी कठिन था कि माओवाद के नासूर को नष्ट किया जा सकता है। एक साल में 2 सौ से अधिक माओवादियों को मार गिराया। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से माओवाद की जड़ से मुक्त हुए गांवों में पुन: विकास की रोशनी पहुंची है। हमने नई उद्योग नीति तैयार की है, जिसमें अगले पांच सालों में ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से पांच लाख रोजगार सृजित करेंगे। हमने शासकीय सेवाओं में हजारों पदों में भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री नड्डा को बस्तर के कलाकारों द्वारा बेल मेटल से निर्मित अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक द्वारा राज्य शासन की योजनाओं पर रेत से तैयार की गई कृति का प्रदर्शन किया गया।

प्रियंका का संसद में पहला भाषण

अपनों पर साधा निशाना

नई दिल्ली। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर कटाक्ष करते हुए, भाजपा आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने आज एक वीडियो साझा किया, जिसमें प्रियंका गांधी भाजपा सरकार की आलोचना करने की कोशिश करते हुए अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार पर निशाना साध रही हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने जाहिर तौर पर जुबान फिसलते हुए बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में सभी कानून बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की आलोचना की। एक्स पर वीडियो साझा करते हुए, मालवीय ने कहा कि यह अपने भाई राहुल गांधी की तरह जागरूकता की कमी का एक और उदाहरण है। उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की आलोचना की, वे इस बात से अनभिज्ञ थीं कि उनकी अपनी पार्टी, कांग्रेस, वहां सत्ता में है।

यह किसी नेक इरादे से प्रेरित नहीं है- यह उनके भाई राहुल गांधी की तरह जागरूकता की कमी का एक और उदाहरण है। राजनीतिक सर्कस तो अभी शुरू हुआ है। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर एक चर्चा के दौरान बोलते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कथित तौर पर एक व्यक्ति (अडानी) का पक्ष लेने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। या एक व्यक्ति सब कुछ बदला जा रहा है।

आज की सरकार ने सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे दिए हैं, हिमाचल के सेब उत्पादक रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। एक व्यक्ति का पक्ष लिया जा रहा है और 142 करोड़ भारतीयों की अनदेखी की जा रही है। रेलवे, हवाई अड्डे आदि सभी व्यवसाय एक ही व्यक्ति को दिये जा रहे हैं।

प्रियंका राहुल के राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा- कांग्रेस नेता के पहले भाषण पर बोली भाजपा

भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती हैं, अगर लोकसभा में उनके पहले भाषण को कोई संकेत माना जाए। निचले सदन में हिंदी में दिए गए अपने 32 मिनट के भाषण में, प्रियंका गांधी आक्रामक लेकिन संयमित दिखीं, उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई, जबकि उन्होंने विपक्ष के प्रमुख मुद्दों को उठाया। इसमें संविधान को बदलने के भाजपा के कथित प्रयास, अदाणी समूह का बढ़ता एकाधिकार, महिलाओं पर अत्याचार, संभल और मणिपुर में हिंसा की घटनाएं और देश भर में जाति जनगणना की मांग शामिल थी। उनके भाषण पर टिप्पणी करते हुए, अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अगर प्रियंका वाड्रा के पहले भाषण को कोई संकेत माना जाए, तो वे राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, न केवल उत्तराधिकारी के रूप में, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सार्वजनिक चर्चा में हल्केपन का स्तर बढ़ाने में उनसे आगे निकल सकती हैं।

कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर तीखा हमला बोला

लोकसभा में संविधान पर बहस में हिस्सा लेते हुए केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझ में नहीं आया है कि यह भारत का संविधान है न कि संघ का विधान। उन्होंने कहा कि संविधान न्याय, एकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सुरक्षा कवच है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इसे तोड़ने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आते तो सत्तारूढ़ भाजपा संविधान में बदलाव करना शुरू कर देती।

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने की प्रियंका के भाषण की तारीफ

वहीं प्रियंका गांधी के भाषण के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, %शानदार भाषण...मेरे पहले भाषण से भी बेहतर, इसे ऐसे ही कहें।% जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी उनके भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह %शानदार% था। उन्होंने सरकार के सामने जो भी तथ्य रखे...हम उनके प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी लोकसभा में प्रियंका गांधी के पहले भाषण की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार सांसद बनने वाली महिला की तरह बात नहीं की और उन्होंने सरकार को सही तौर पर बताया कि उसे अतीत पर बात करने के बजाय वर्तमान समय के बारे में बात करनी चाहिए।

प्रमुख समाचार

मोइत्रा के जज लोया की मौत का जिक्र करने पर लोस में हंगामा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से न्यायाधीश बीएच लोया की मौत का जिक्र अपने समय से बहुत पहले किए जाने से शुक्रवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा मच गया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से सुलझाए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया और उचित संसदीय कार्रवाई की चेतावनी दी। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित बहस में भाग लेते हुए, महुआ मोइत्रा ने बीएच लोया की मृत्यु पर एक संक्षिप्त, लेकिन विवादास्पद टिप्पणी की, क्योंकि उन्होंने आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के लिए संस्थानों और विपक्षी नेताओं को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला किया। इस मामले पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार थोड़ी-थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने किया तलब

लखनऊ। भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान अपने भाषण में सावरकर के कथित अपमान वाली अर्जी की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को एमपी एमएलए अदालत के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख नियत करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को अदालत में तलब किया है। कोर्ट में वादी नृपेंद्र पांडे की ओर से दी गई दलील में कहा गया कि 12 नवंबर 2022 को एक समाचार चैनल पर प्रसारित राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी जुड़े हुए भारत को पुन: जोड़ने की बात कहते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सोची-समझी रणनीति एवं षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के अकोला में 17 नवंबर को समाज में वैमनस्यता और द्वेष फैलाने की मंशा से भारतीय इतिहास और राष्ट्रवादी विचारधारा के महानायक सावरकर की सार्वजनिक मंच से अमर्यादित आलोचना की और देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान सभी समाचार प्रतिनिधियों को पहले से छापे पत्रक वितरित किए जो इस बात का प्रमाण है कि सावरकर के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से पत्रक तैयार कराया गया।

मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग

नई दिल्ली। कुछ सांसदों ने नोबल कमेटी को पत्र लिखा है कि मोहम्मद यूनुस का नोबल शांति पुरस्कार की फिर से समीक्षा की जाए। इस विषय पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है। एक सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि ये सवाल नोबल लॉरेट कमेटी से पूछिए। हमारे पास इसका जवाब नहीं है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कथित दमन और नरसंहार के खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों ने गुरुवार को शिमला में प्रदर्शन किया और पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने की मांग की। डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स (डीएचआर) के बैनर तले सामाजिक संगठनों के साथ शामिल होकर, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सदस्यों और उनके पूजा स्थलों पर कथित अत्याचारों पर गुस्सा व्यक्त किया और अपनी सरकार से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। डीआरएच संयोजक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस के सलाहकार बनने के बाद से हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों पर हमले लगातार जारी हैं।

हरियाणा से रास सांसद चुनी गईं भाजपा की रेखा शर्मा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा शुक्रवार को हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुनी गईं। उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से अपना प्रमाण पत्र लेते समय सोशल मीडिया पर दृश्य सामने आए। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि लोगों की आवाज उठाना मेरी प्राथमिकता है। राज्यसभा में उम्मीदवार इसलिए भेजा जाता है ताकि वे लोगों की आवाज उठा सकें। मैं महिला आयोग से आई हूं, 9 साल काम किया है। इसलिए, मैं उनके सशक्तिकरण के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करूंगी। रेखा शर्मा ने मंगलवार को यहां हरियाणा से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। वह मैदान में अकेली उम्मीदवार थीं। भाजपा ने सोमवार को 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए शर्मा के नाम की घोषणा की थी। हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के साथ शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र दिया।

दिल्ली भाजपा ने डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज की

नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर दिल्ली की मतदाता सूची में लाखों अवैध घुसपैठियों (रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के), डुप्लीकेट, फर्जी पते वाले और मृत लोगों के नाम शामिल होने का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इन शिकायतों को प्राथमिकता से कानूनी आधार पर हल करे ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हों। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी की चुनाव समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक ओम पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता सुबांसुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक अधिवक्ता संकेत गुप्ता शामिल थे। वीरेंद्र सचदेवा ने श्वेतपत्र को 5000 पन्नों के प्राथमिक सबूतों के साथ विस्तृत प्रस्तुति दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को बताया कि यह हैरानी की बात है कि हर बार लोकसभा चुनाव समाप्त होने और विधानसभा चुनाव शुरू होने के बीच लाखों नए मतदाता पंजीकृत होते हैं। यह संख्या वार्षिक मतदाता सारांश संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से काफी अधिक होती है।

छत्तीसगढ़ में सुशासन का एक वर्ष

चन्द्र शेखर गंगराड़े

चतुर्थ विधान सभा के आम चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला और श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तब 'भूपेश है तो भरोसा है' के नारे के साथ, कांग्रेस पार्टी पंचम् विधान सभा के आम चुनाव में उतरी थी लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने 'भूपेश है तो भरोसा है' के नारे पर भरोसा न कर, 'मोदी की गारंटी' पर विश्वास व्यक्त किया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जिसके मुखिया के रूप में पार्टी ने सहज, सरल, सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया. इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का युग प्रारंभ हुआ और डबल इंजन की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ ने विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ना प्रारंभ किया.

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के एक वर्ष के कार्यकाल में उल्लेखनीय उपलब्धियों की यदि यहां चर्चा की जाये तो इस एक वर्ष में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का दूरगामी असर छत्तीसगढ़ के विकास पर आगामी दो-तीन वर्षों में परिलक्षित होगा लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है जो उनकी सादगी, सहजता, सरलता, सौम्यता है, उससे उनकी प्रशासनिक कुशलता का परिचय मिलता है. बड़ी ही सहजता से कठोर निर्णय लेने से भी वे नहीं चूकते. नक्सल अभियान में जो सफलता विगत एक वर्ष में हासिल हुई है, वह इसका जीवंत उदाहरण है और जिस प्रकार नक्सलियों से मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश शीघ्र ही नक्सलमुक्त होने की दिशा में अग्रसर है. साथ ही नक्सली क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने 'नियद नेल्लानार योजना' की शुरूआत की है और प्रशासन इस योजना पर प्राथमिकता से कार्य कर रहा है. साथ ही नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री की सहजता, सरलता का एक

और उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब महतारी वंदन योजना की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही थी तो एक आम महिला जो उनसे मिलने आई थी, उससे ही उन्होंने राशि ट्रांसफर करवा कर, एक आम महिला को सम्मान दिया.

विष्णु के सुशासन का एक वर्ष पूर्ण होने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को बने 24 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर, रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है और उसकी औपचारिक शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर के दिन से हो रही है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सहित संपूर्ण देश में 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है, से हो रही है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के साथ ही मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पहल प्रारंभ कर दी.

इस अवधि में उन्होंने शराब माफिया पर नकेल कसते हुए शराब के व्यवसाय में बिचौलिया की इंट्री खत्म कर दी और सीधे शराब निर्माता कंपनियों से शराब क्रय की नीति लागू की जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, साथ ही धान की मीलिंग में जो दिक्कतें थी, उसे दूर करते हुए मीलिंग चार्ज को कम कर दिया, जिससे प्रदेश के राजस्व की बचत भी हो रही है.

इस एक वर्ष के कार्यकाल में श्री विष्णु देव साय की सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम, संपत्ति के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में सुधार और सिस्टम में पारदर्शिता लाना है और इसके साथ ही मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से गवर्नमेंट गाईड लाईन दर पर ही मकानों के क्रय विक्रय पर रजिस्ट्री शुल्क लेने का निर्णय लिया गया, जिससे ऐसे मध्यमवर्गीय परिवार, जिनके पास स्वयं की बचत नहीं होती थी और वास्तविक विक्रय मूल्य की राशि पर बैंक से ऋण लेना पड़ता था, उन्हें काफी राहत मिलेगी.

विष्णु के सुशासन की मॉनीटरिंग के लिए भी एक पृथक से 'सुशासन विभाग' बनाया गया है, ताकि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा सके.

हाल ही में उनकी एक दूरदर्शी सोच के कारण जशपुर जिले का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल पर्यटन के मानचित्र में तेजी से उभरा है. प्रदेश के 'मधेश्वर पर्वत' को पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान प्राप्त हुई है. मधेश्वर को सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है.

इस प्रकार इस एक वर्ष में मुख्यमंत्री ने अपने सहज, सरल स्वभाव के कारण न केवल छत्तीसगढ़ के विकास को गति दी है, वहीं जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण के लिए जनदर्शन के माध्यम से उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास भी किया गया है, जिससे जनमानस के मन में न केवल उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत हुआ है बल्कि उनके सुशासन के प्रति भी आम जन में विश्वास की भावना परलक्षित हो रही है. 13 दिसम्बर को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृपया उक्त आलेख आपके समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। धन्यवाद

बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़, दो नक्सली ढेर

■ 12 बोर बंदूक, विस्फोटक बरामद

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर के नेंड्रा-पुन्नुर के जंगल में चल रही मुठभेड़ में दो नक्सलियों के ढेर होने के खबर सामने आई है। बता दें कि, डीआरजी, कोबरा 210 और 168 वाहिनी केरिपु यंग प्लाटून की संयुक्त टीम के साथ शुक्रवार सुबह बासागुड़ा थाना क्षेत्रान्तर्गत नेण्ड्रा-पुन्नुर के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद मौके से 12 बोर गन, 01 भरमार, प्रिंटर, पिट्ठू, माओवादी वर्दी, साहित्य, विस्फोटक तथा अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई।

दरअसल, थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत नेण्ड्रा-पुन्नुर में मद्देड़ एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों के मुठभेड़ साथ विगत दिनों थाना बासागुड़ा तर्रेम क्षेत्र में हुए ग्रामीणों की हत्या में शामिल माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, कोबरा 210 एवं यंग प्लाटून 168 वाहिनी केरिपु की संयुक्त टीम दिनांक 12 दिसंबर की रात्रि में नेण्ड्रा-पुन्नुर की ओर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान आज सुबह 7.30 बजे पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमे 02 माओवादी मारे गए। एसपी ने

मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, घटना में मारे गए माओवादियों की शिनाख्तगी एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही थाना बासागुड़ा द्वारा की जा रही है। विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। इधर, बीते गुरुवार को नारायणपुर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि, कल कल अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था। सूचना मिली है कि, सभी नक्सलियों के शव को नारायणपुर मुख्यालय भेजा गया है।

मुनगा मुठभेड़ में मारा गया था पाण्डु, पुलिस ने की शिनाख्त, एनकाउंटर में कई नक्सली घायल

बीजापुर। बीजापुर में बुधवार को गंगालुर थाना क्षेत्र के मुनगा के जंगल में सुरक्षाबलों व नक्सलियों की कंपनी नम्बर दो के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि गंगालुर थाना क्षेत्र के मुनगा के जंगल पहाड़ में जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की पहचान गंगालुर एरिया कमेटी प्लाटून डिप्टी कमाण्डर पाण्डु माड़वी पिता आन्दो माड़वी निवासी नयापारा ग्राम मुंगा के रूप में हुई है। मुठभेड़ के बाद

घटनास्थल से जवानों ने नक्सली के शव में साथ 1 नग 9 द्वद्व पिस्टल, 1 नग टिफिन बम, 1 नग कुकर बम सहित विस्फोटक पदार्थ व अन्य रोजमर्रा की सामग्री बरामद की थी। पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए है या घायल हो हुए है।

नक्सल संगठन में सक्रिय 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुनर्वास नीति एवं नियद नेल्ला नार योजना तथा अति-संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप नक्सली संगठन में सक्रिय 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

आत्मसर्पित नक्सलियों में 1. जोगेन्द्र यादव पिता सुक्को (पेद्दाबोडकेल आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष) 2. हेमला देवा पिता स्व. हुंगा (पेद्दाबोडकेल आरपीसी जनसर्म्पक कमेटी अध्यक्ष) 3. माड़वी गंगा पिता स्व. नंगा (पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य) 4. मड़कम नंगा पिता स्व. मंगडू (पेद्दाबोडकेल आरपीसी संघम सदस्य) 5. मड़कम मुकेश पिता स्व. देवा (पेद्दाबोडकेल आरपीसी जीआरडी मिलिशिया सदस्य) 6. हेमला जोगा पता स्व. देवा (पेद्दाबोड़केल आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य) 7. बारसे लखमा पिता हिंगा (जीआरडी मिलिशिया सदस्य) 8. सोड़ी मुक्का पिता हिड़मा (डीएकेएमएस सदस्य) 9. मड़कम हुंगा पिता स्व.मड़कम केसा (पूवर्ती आरपीसी भुमकाल मिलिशिया सदस्य) 10.

माड़वी पोज्जा पिता लखमा (पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य) 11. हेमला सुक्का पिता भीमा (बासागुड़ा एलओएस सदस्य) ने सुकमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अमित प्रकाश, द्वितीय कमान अधिकारी 131 वाहिनी सीआरपीएफ, रवि गनवीर उप कमाण्डेन्ट 74 वाहिनी सीआरपीएफ, निरीक्षक पवन कुमार 223 वाहिनी सीआरपीएफ, निरीक्षक अरिओम प्रकाश 150 वाहिनी सीआरपीएफ एवं निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत प्रभारी नक्सल सेल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

नक्सली बारसे लखमा पिता हिंगा, सोड़ी मुक्का पिता हिड़मा को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 74 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा, नक्सली मड़कम मुकेश पिता स्व. देवा, हेमला जोगा पिता स्व. देवा आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 131 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा, नकसली मड़कम नंगा पिता स्व. मंगडू को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 150 वाहिनी सीआरपीएफ, 201 कोबरा वाहिनी के आसूचना शाखा, नक्सली माड़वी पोज्जा पिता लखमा, हेमला सुक्का पिता भीमा, को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 223 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा एवं नक्सली, जोगेन्द्र यादव पिता सुक्का, हेमला देवा पिता स्व. हुंगा, माड़वी गंगा पिता स्व. नंगा एवं बारसे लखम पिता हिंगा को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में डीआरजी टीम का योगदान रहा। उक्त सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति'' के तहत् सहायता राशि व अन्य सुविधायें प्रदाय कराये जायेंगे।

कलेक्टर ने जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अध्यक्ष को हटाया

6 वर्ष तक चुनाव लडऩे पर लगा प्रतिबंध

बीजापुर। जिले के जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अध्यक्ष दशरथ कुंजाम को बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने 15वें वित्त से भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के बाद सही पाये जाने पर धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए जनपद पंचायत भैरमगढ़ अध्यक्ष के पद से हटा दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर के अजय सिंह ने जनपद पंचायत अध्यक्ष दशरथ कुंजाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए तत्कालीन कलेक्टर अनुराग पांडे से शिकायत की थी। इसके बाद मामले में जांच में अधिकारियों ने पाया कि जपं अध्यक्ष की पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। उनके नाम से ही बनी फर्म से लाखों रुपए की खरीदी की गई है। इसके अलावा भी कई कामों में आर्थिक अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद कलेक्टर ने धारा 40 का उपयोग करते हुए जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अध्यक्ष दशरथ कुंजाम को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अध्यक्ष दशरथ कुंजाम पर आने वाले 6 वर्षों तक किसी भी प्रकार का चुनाव लडऩे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि इधर इस तरह से बीजापुर जिले में जनपद पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाने और 6 वर्ष तक चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध का यह पहला मामला है। इलाके में सरपंच स्तर के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती रही है, लेकिन जनपद पंचायत अध्यक्ष पर इस तरह से सीधी कार्रवाई का पहला मामला हैं।

शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही

अर्धवार्षिक परीक्षा में बीते साल के प्रश्न पत्र को किया हूबहू रिपीट

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के चलते जिले के 1200 से अधिक सरकारी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूल के अर्धवार्षिक परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। दरअसल, कल 12 दिसंबर गुरुवार को शुरू हुई परीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने प्रश्न पत्र छपवाया था। इस प्रश्न पत्र में भारी गड़बड़ी थी, बीते साल 2023 के प्रश्न पत्र को रिपीट किया गया था। इस बात की जानकारी विभाग को मिली तो आनन-फानन में आज शुक्रवार को कक्षा एक से 8वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है।

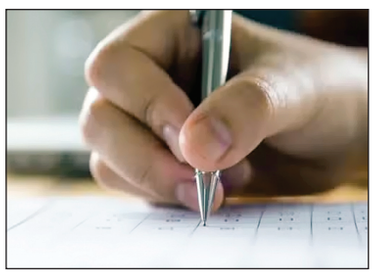

ऐसे में अब शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। यही कारण है कि छग टीचर्स एसोसिएशन ने अर्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद अचानक स्थगित करने पर सवाल खड़ा किया है। जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा पहली से आठवीं तक कि अर्धवार्षिक परीक्षा 12 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाना था, जिसके अनुसार 12 दिसंबर को सभी कक्षा के एक विषय का परीक्षा सम्पन्न भी हो गया है।

इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 12 दिसंबर देर शाम को जारी पत्र के अनुसार अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद अचानक स्थगित कर दिए जाने पर सवाल खड़ा किया जाना स्वाभाविक है। इससे हजारों विद्यार्थी, शिक्षक व पालकों की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ता है। जनमानस में विभाग की छवि धूमिल भी होता है। इससे समय, धन व ऊर्जा का अपव्यय भी होता है। बता दें कि इस परीक्षा में पूरे जिले से कक्षा एक से 8वीं तक करीब एक लाख 10 हजार से अधिक बच्चे शमिल होने वाले थे।

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में नगरीय निकाय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

चिरमिरी नगर पालिका निगम में कामकाज पूरी तरह से ठप

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ के 184 नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। चिरमिरी नगर पालिका निगम के कर्मचारियों ने भी इस आंदोलन में भाग लेते हुए अपना कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है।

हड़ताल की अगुवाई कर रहे कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों में ट्रेजरी से वेतन भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति बहाली, छठे और सातवें वेतनमान का एरियर, नियमित वेतनमान के साथ पदोन्नति, ठेका प्रथा की समाप्ति और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को शामिल किया है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी कर्मचारियों के इस आंदोलन का समर्थन किया है। पार्टी के प्रतिनिधि चिरमिरी नगर निगम पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन पत्र सौंप चुके हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चिरमिरी के ब्लॉक अध्यक्ष शेख इस्माइल ने बताया कि पिछले कई महीनों से नगर पालिका निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार आवेदन दिए, मनेंद्रगढ़ जिला कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन बातों को नकारते हुए वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर्मचारियों के साथ है।

नव युवक अधिकारी कर्मचारी संघ के जिला मंत्री पदमा राव ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे जिला पदाधिकारी पंचूराम साहू ने कहा कि जब तक हमारी सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

हड़ताल के कारण नगर निगम की अधिकांश सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। मीडिया प्रभारी अनूप वर्मा ने बताया कि ट्रेजरी बंद होने के कारण वेतन समय पर नहीं मिल पाता है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आक्रोशित हैं। सभी कर्मचारी एकमत होकर इस आंदोलन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हड़ताल के चलते नगर निगम के दैनिक कार्यों पर बड़ा असर पड़ा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ के शिमला में पारा पहुंचा तीन डिग्री सेल्सियस

अंबिकापुर। उत्तरी छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बेमौसम बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में ठंड बढऩे लग गया है शीतलहर चलने से लोग बेहाल हैं। इसी का परिणाम हैं कि सरगुजा संभाग में तापमान में भारी गिरावट के साथ कोहरे छाने लग गए है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में इस सीजन में पहली बार पाला जमा और यहां का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैनपाट में इस सीजन में पहली बार पाला जमा। यहां का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण कंपकंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहां का पारा सात डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। शीतलहर चलने से लोग बेहाल हैं। दिन में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सरगुजा कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। इधर, मैनपाट के नर्मदापुर, कमलेश्वरपुर सहित आसपास के इलाके में पाला जमा रहा।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु 20 तक आवेदन आमंत्रित

गौरेला पेंड्रा मरवाही। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर के निर्देशानुसार जिले के चयनित 272 विद्यालयों में 30 दिनों का रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना है। इच्छुक प्रशिक्षकों से 20 दिसम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्रशिक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रशिक्षकों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षक जुड़ो, कराटे, ताईक्वांडो, किंक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट में दक्ष होना चाहिए। प्रतिदिन प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 30 मिनट की होगी। आवेदन के साथ 01 फोटो, हायर सेकेण्डरी स्कूल की मार्कशीट, विधा में दक्ष प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के मो.नं. +91-9340456178 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशिक्षण के लिए प्रति शाला 5 हजार रूपए स्वीकृत है, जो संबंधित शालाओं द्वारा भुगतान किया जाएगा।

दूरबीन पद्धति से अस्थि रोग का ऑपरेशन शुरू

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिला चिकित्सालय में लगातार स्वास्थ सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी की विशेष पहल और उनके द्वारा राशि स्वीकृत करने पर जिला चिकित्सालय में सी-आर्म मशीन से दूरबीन पद्धति से अस्थि रोग का ऑपरेशन शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा ने बताया कि सी-आर्म मशीन नई तकनीक का मशीन है, इससे कम चीड़-फाड़ से दूरबीन पद्धति से फैक्चर हड्डी को जोड़ा जाता है। इससे मरीज को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

महंत के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने गर्म कपड़ों का किया वितरण

चिरमिरी। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के जन्मदिन के अवसर पर पार्षद एवं कांग्रेसी नेता शिवांश जैन के नेतृत्व में शासकीय स्कूल, हल्दीबाड़ी में जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने डॉ. महंत के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सुभाष कश्यप, उमाशंकर अलगमकर, विनय सा, लाल बाबू, असरफ अली परवेज, और प्रशांत धीरज सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शिवांश जैन ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना और समाज में एक सकारात्मक संदेश देना है। इस अवसर पर, उन्होंने और अन्य नेताओं ने डॉ. चरणदास महंत के समाज सेवा और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉ. महंत के जन्मदिन को इस प्रकार सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए कांग्रेसजनों ने न केवल उनकी विचारधारा का अनुसरण किया, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया।

88 क्विंटल अवैध धान परिवहन के साथ तीन वाहन जब्त

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले में अवैध धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई जारी है। धान उपार्जन केंद्रों में कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान लाने की कोशिशों पर प्रशासन की पैनी नजर है। इसी क्रम में रेंगाखार क्षेत्र के सिवनी खुर्द चेक पोस्ट पर बीती रात तहसीलदार अखिलेश ध्रुव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन गाडियों को अवैध धान लाते हुए पकड़ा गया। वाहनों में लदे धान की जांच की गई, जिसमें पिकअप वाहन सीजी 07सी 5565 पर 28 क्विंटल, माजदा वाहन 5252 एक्स पर 40 क्विंटल, और पिकअप वाहन सीजी 07 बीयू 9241 पर 20 क्विंटल धान लदा हुआ मिला। यह धान मध्यप्रदेश के बिटली और मंडाई गांव से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था, जिसे रेंगाखार क्षेत्र की समितियों में बेचने का प्रयास था। मौके पर तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धान को जप्त कर थाने में सुपुर्द कर दिया। जप्त धान पर मंडी निरीक्षक पवन शर्मा ने मंडी अधिनियम के तहत विधिवत कार्रवाई की।

पांच थानों की पुलिस ने नागरिकों का किया वेरीफिकेशन

बांग्लादेशी नागरिक होने की आशंका, 21 संदिग्धों को पूछताछ के लिए ले गई थाने

दुर्ग। दुर्ग में बांग्लादेशी नागरिक होने की आशंका से पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र नई बस्ती में पुलिस की अचानक धमक देखने को मिली। पांच थानों के पुलिस बल के साथ बस्ती में रहने वाले नागरिकों का वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान किसी भी घर से कोई भी अवैध हथियार नहीं मिल पाया है। वहीं 21 संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुरानी भिलाई थाना लाया गया।

नई बस्ती में रहवासियों की पहचान के लिए शुक्रवार सुबह से वेरिफिकेशन प्रारंभ किया गया। इस संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया।इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिलाई शहर सुखनंदन राठौर, भिलाई - चरोदा निगम कमिश्नर दर्शन सिंह राजपूत, तहसीलदार एवं पांच थाने जामुल, छावनी, खुर्सीपार, भिलाई-3 एवं कुम्हारी का पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस की इस औचक कार्रवाई को कुछ दिन पहले प्रदेश के गृहमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के दुर्ग में दिए गए उस बयान से जोड़कर देखा

जा रहा है जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने अभियान चलाने की बात कही थी जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है।

भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के हथखोज वार्ड में औद्योगिक विकास निगम की खाली जमीन पर एक नई बस्ती बस गई है इस बस्ती में रहने वाले ज्यादातर परिवार बांग्लाभाषी और धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले हैं इस वजह से गाहे-बगाहे इस बस्ती के ज्यादातर लोगों पर बांग्लादेशी घुसपैठी होने की आशंका स्थानीय नागरिक जताते रहे हैं। वैसे यह बस्ती पुरी तरह से एकाएक आबाद नहीं हुई, बल्कि धीरे-धीरे लोग बाहर से आकर यहां अवैध कब्जा कर बसने लगे।

भिलाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि पुलिस के द्वारा जिला और नगर निगम प्रशासन के साथ हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया की नई बस्ती में बाहरी लोगों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पार्षद एवं वहां के निवासियों से वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया था। परंतु संबंधित लोगों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिस टीम ने यहां पहुंचकर लोगों की पहचान हेतु प्रमाणिक दस्तावेज की जांच हेतु अभियान चलाया इस दौरान लोगों के पास स्थानीय और बाहर के आधार कार्ड मिले हैं पूछताछ में पता चला है कि लोग चार साल, दो साल और छह महीने पहले आकर बस्ती में रह रहे हैं। कुछ लोगों की लोगों को थाने में ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है।

परीक्षा के दिन 14 बच्चे खेल रहे थे स्कूल से बाहर

■ प्रधानपाठक व अन्य दो शिक्षकों को शोकाज कारण बताओ नोटिस जारी

बेमेतरा। बेरला विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश कर्माकर व सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी नारायण ठाकुर ने मटिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का गुरुवार को औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान प्रधानपाठक उत्तरा प्रसाद बंजारे अनुपस्थित पाए गए। साथ ही चौथी कक्षा के सभी 14 बच्चे स्कूल के बाहर 600 मीटर दूर मिले। हैरत की बात यह भी है कि बाकी दो शिक्षक अजयशंकर मिर्चे व ईरज कुमार वर्मा को चौथी कक्षा के बच्चों के गायब होने की सूचना तक नहीं थी। इस पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कर्माकर ने नाराजगी जाहिर की और प्रधानपाठक व अन्य दो शिक्षकों को शोकाज कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उचित जवाब नहीं आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मालूम हो कि प्राथमिक शाला मटिया में बच्चों की गुरुवार से सुबह 11 बजे से पहली से लेकर पांचवीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा थी। किंतु प्रधानपाठक उत्तर प्रसाद बंजारे 12 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचे थे। इस कारण पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी की परीक्षा संचालित हो रही थी और चौथी कक्षा की परीक्षा संचालित नहीं थी और और बच्चे बाहर घूम रहे थे। इस पर चौथी कक्षा की छात्रा साक्षी साहू ने अपने पालक पंचराम साहू को बताया कि बंजारे सर नहीं आए हैं इस कारण हमारी परीक्षा नहीं हो रही है। चौथी कक्षा के 14 बच्चे स्कूल के बाहर घूम रहे थे। पालक पंचराम साहू ने इसकी शिकायत भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र वर्मा से की। तभी पालक पंचराम साहू द्वारा बच्चों के साथ संकुल समन्वयक सुरेंद्र पटेल के पास पहुंचे। तत्पश्चात बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे फिर चौथी कक्षा के बच्चों की परीक्षा शुरू की गई। बेरला के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश ने कहा कि कोई भी शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षक समय पर उपस्थित होकर बच्चों की बेहतर पढ़ाई पर फोकस करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ के जनादेश परब में शामिल होने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा रायपुर पहुंचे

रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत

प्रकाश नड्डा शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित जनादेश परब में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री नड्डा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा सहित स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, श्री सुनील सोनी एवं श्री किरण देव सिंह ने भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया।

अब तक 45.78 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जारी है। धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों का मॉनिटरिंग भी जारी है। राज्य में धान 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक 45.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 9.79 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत दस हजार एक करोड़ 13 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगी। धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स ने धान का उठाव भी शुरू कर दिया है। धान उठाव के लिए 2.51 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किया गया था, जिसके खिलाफ 51 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। इस साल 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 12 दिसंबर को 67479 किसानों से 2.66 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 92 हजार से अधिक टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 93160 टोकन जारी किए गए हैं। राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत और निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए है, जिसका नंबर 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

नगर निगम चुनाव के लिए व्यय सीमा तय

रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग ने आगामी दिनों होने वाले चुनाव के लिए व्यय सीमा तय कर दी है। राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार निगम के प्रत्याशी 5-8 लाख, पालिका के 2 लाख और नगर पंचायत में 75 हजार खर्च कर सकेंगे।

लक्ष्मीनारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया वार्षिक उत्सव

रायपुर। लक्ष्मीनारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव रंगमन्दिर प्रेक्षागृह गांधी चौक में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वर्षा वरवंडकर चीफ कॅरियर काउन्सलर माय अगला कदम डॉट कॉम उपस्थित हुई। अध्यक्षता भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति के अध्यक्ष तरल मोदी तथा अजय तिवारी ने किया। शाला का प्रतिवेदन प्राचार्या श्रीमती मनीषा गहोई ने प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण सचिव श्रीमती शोभा खंडेलवाल दिया एवं कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्रीमती संध्या दुबे ने किया। अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को आशीर्वचन एवम उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

आज भीमसेन भवन में अग्रवाल समाज मनाएगा महालक्ष्मी वरदान दिवस

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रांतीय युवा अग्रवाल मंच के संरक्षक कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि शनिवार, 14 दिसंबर को शाम 6 बजे श्री रामनाथ भीमसेन सभा भवन में महालक्ष्मी वरदान दिवस के अवसर पर कुलदेवी महालक्ष्मी एवं भगवान अग्रसेन की पूजा आरती के साथ प्रसाद रखी गई है। महामंत्री नितेश अग्रवाल ने बताया कि अगहन मास की पूर्णिमा के दिन ही अग्रसेन जी की लंबी तपस्या के पश्चात मां लक्ष्मी ने दर्शन देकर वरदान दिया था की मैं तुम्हारे कुल में हमेशा वास करूंगी। इसीलिए अगहन मास की पूर्णिमा के दिन को अग्रवाल समाज पूरे देश में महालक्ष्मी वरदान दिवस के रूप में मनाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से अग्रवाल समाज के परिवार में समृद्धि के साथ सुख शांति है। समाज बंधु साथ मिलकर मां लक्ष्मी की पूजा आरती पूरे उल्लास और भक्ति के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रांतीय युवा अग्रवाल मंच ने समाज बंधुओ से सपरिवार महालक्ष्मी वरदान दिवस में शामिल होकर पूजा अर्चना करने हैं के साथ प्रसादी लेने की अपील की है।

आईपीएस जीपी सिंह के सहयोगी रणजीत सिंह सैनी को हाई कोर्ट से राहत

कांग्रेस सरकार के समय दर्ज एफआईआर को किया खारिज

बिलासपुर। कारोबारी से वसूली के मामले में आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह के साथ आरोपी बनाए गए उद्योगपति रणजीत सिंह सैनी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। उनके खिलाफ वर्ष 2021 में सुपेला पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। मामले में पहले ही आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया जा चुका है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने रणजीत सिंह सैनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु पांडेय के तर्कों को सुनने के बाद फैसला देते हुए बेंच ने माना कि समान आरोप पर इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ एफआईआर को पहले ही खारिज कर दिया है। ऐसे में

याचिकाकर्ता को भी यही लाभ दिया जाना चाहिए।

बेंच ने माना कि इसके अलावा याचिकाकर्ता किसी उच्च पद पर नहीं है, ऐसे में अभियोजन पक्ष का पूरा मामला फर्जी प्रतीत होता है। ऐसे में सुपेला थाना में 27 जुलाई 21 को दर्ज एफआईआर को रद्द करने के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा 27 मई 2022 का आदेश और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने का 12 मार्च 2024 का आदेश को निरस्त कर दिया है।

मामले में रणजीत सिंह सैनी के अधिवक्ता हिमांशु पांडेय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कोर्ट ने कहा कि चूंकि रणजीत सिंह इतने बड़े पद पर नहीं हैं, जो केस को प्रभावित कर सकें। यह फंसाने के लिए झूठा केस किया गया था। इस आधार पर कोर्ट ने एफआईआर, चार्जशीट और आगे की कार्रवाई को खारिज कर दिया है।

बता दें कि कमल सूर्या विहार स्मृतिनगर में रहने वाले कमल सेन ने वर्ष 2007 में हथखोज में श्याम कैमिकल नाम से व्यवसाय शुरू किया। फैक्ट्री में छत्तीसगढ़ पुलिस ने दबिश दी। कमल और फैक्ट्री के कर्मचारी प्रकाश चक्रधारी और भेग सिंह पुलिस महासमुंद ले गई, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके करीब 6 महीने बाद इस पूरे मामले में कमल सेन को जमानत मिली थी।

कमल की पत्नी ने आरोप लगाया कि आईपीएस जीपी सिंह के सहयोगी रणजीत ने उनसे संपर्क कर चालान में धाराएं कम करने और जल्दी पेश करने के एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। 20 लाख रुपए बतौर एडवांस देने पर मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कमल सेन की पत्नी, दोस्त और साला तीनों से 5 जुलाई 2016 को रणजीत सिंह घर गए, जहां से सभी जीपी सिंह के पेंशन बाड़ा स्थित मकान पर गए। यहां रुपए लिए गए।

मामले में छह साल बाद 28 जुलाई 2021 को कमल सेन की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने आईपीएस जीपी सिंह और रणजीत सिंह के खिलाफ धारा 388, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया था। मामले में सुपेला पुलिस ने रणजीत सिंह सैनी को गिरफ्तार किया था।

छत्तीसगढ़ के 26 मजदूर कर्नाटक में बनाए गए बंधक

मोहला-मानपुर। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को दूसरे राज्यों में बंधक बनाकर काम कराने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में मोहला-मानपुर के 36 मजदूरों को महाराष्ट्र से छुड़ाया गया था। अब फिर से इसी जिले के 26 ग्रामीण मजदूरों को कर्नाटक में बंधुआ मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। मजदूरों ने एक वीडियो बनाकर अपने गांव वालों को भेजकर मदद की गुहार लगाई है।

नक्सल प्रभावित और आदिवासी बाहुल्य मोहला-मानपुर जिले के ग्राम हालमकोड़ों और मोहगांव के 26 ग्रामीण, जिनमें 15 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं, कर्नाटक के बेलहोंगल क्षेत्र में बंधक बनाए गए हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के निवासी तथाकथित ठेकेदार उद्धव श्री किशन तिडके इन मजदूरों को मजदूरी के नाम पर लेकर गया था। बंधक मजदूरों ने चोरी-छिपे एक वीडियो बनाकर अपने गांववालों को भेजा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मजदूरों को सामान ढोने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जब वे भागने की कोशिश करते हैं, तो ठेकेदार के आदमी उन्हें रोकते और डराते हैं। हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने मजदूरों द्वारा भेजे गए वीडियो को मीडिया से साझा कर मदद की अपील की है। आवेदन में परिजनों ने बताया है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला निवासी तथाकथित ठेकेदार उद्धव श्री किशन तिड़के उनके गांव के 15 महिला और 11 पुरुष कुल 26 ग्रामीणों को मजदूरी कराने के नाम पर अपने साथ ले गया। इन 26 ग्रामीणों को कर्नाटक के बेलहोंगल क्षेत्र में बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है। जिला प्रशासन को दर्खास्त देने के बाद भी मजदूरों की वापसी को लेकर कोई सार्थक प्रशासनिक कार्रवाई सामने नहीं आने पर मजदूरों के परिजनों और ग्रामीणों ने कर्नाटक से बंधक मजदूरों द्वारा भेजे गए वीडियो को मीडिया से साझा किया है।

डॉक्टरों को बताना होगा कितने मरीज डिस्चार्ज हुए, कितने की मौत हुई

रायपुर। रायपुर मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में सेवा दे रहे डॉक्टरों का मूल्यांकन अब सख्त होने जा रहा हैं, अब डॉक्टरों को जानकारी देनी होगी कि यूनिटवाइज कितने मरीज भर्ती हुए, कितनों ने लामा या डामा करवाया, कितने मरीजों की मौत हुई, मरीज रेफर किए हैं तो क्यों, ओपीडी से कितने मरीजों को आईपीडी में भर्ती किया गया आदि। इसके अलावा सर्जिकल विभाग के डॉक्टरों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है।

कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन किरण कौशल ने सभी डीन व अस्पताल अधीक्षकों को पत्र लिखकर डॉक्टरों का मूल्यांकन तत्काल शुरू करने को कहा है। हर माह के पहले सप्ताह में डॉक्टरों के काम की जानकारी सीएमई कार्यालय भेजी जाएगी। वहीं, माह के दूसरे सप्ताह में वीसी के माध्यम से चर्चा होगी। दरअसल, लामा व डामा के केस में परिजन मरीज को आंबेडकर अस्पताल से रिफर करवाकर किसी निजी अस्पताल में ले जाते हैं। इस तरह के केस में कई बार पर्याप्त इलाज नहीं मिलने की बात भी सामने आती रही है। यही नहीं, कुछ जूनियर

डॉक्टर लामा को हथियार बनाकर मरीजों को जबर्दस्ती अस्पताल से चले जाने को कहते हैं। इसमें एक नोटशीट बनती है, जिसमें अटेंडेंट को हस्ताक्षर करना होता है।

अब डॉक्टरों को ये बताना होगा कि उनकी यूनिट में हर माह में कितने मरीज लामा व डामा हो रहे हैं। किसी मरीज की मौत हुई है तो भी उन्हें बताना होगा? हालांकि इसमें नोट करने वाली बात तो है, लेकिन अगर मरीज गंभीर स्थिति में अस्पताल आए तो इसमें डॉक्टरों की लापरवाही नहीं मानी जाएगी। फिर भी यूनिटवाइज मरीजों की मौत की संख्या से कुछ सवाल उठ सकते हैं।

सर्जिकल विभाग के डॉक्टरों के लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। सर्जन को बताना होगा कि कौनसी सर्जरी की, सर्जरी या उसके बाद कॉम्प्लीकेशन तो नहीं हुआ? यही नहीं ये भी बताना होगा कि कितनी सर्जरी की और सर्जरी के दौरान या बाद में कितने मरीजों की मौत हुई? इसके साथ ही डॉक्टरों को अब रिसर्च का टॉपिक और कितने रिसर्च का पब्लिकेशन हुआ, ये भी जानकारी भेजनी होगी। जर्नल का नाम, कॉन्फ्रेंस में साइंटिफिक प्रेजेंटेशन भी बताना होगा। कॉन्फ्रेंस कहां हुआ या क्या अवार्ड मिला, गूगल शीट में ये जानकारी देनी होगी।

इस संबंध में कुछ डॉक्टरों का कहना हैं कि काम करने वाले डॉक्टरों के लिए यह कोई डरने वाली बात नहीं है। डरना तो उन डॉक्टरों को चाहिए जो समय बिताने के लिए कॉलेज या अस्पताल आते हैं। यानी जिनका पूरा ध्यान प्राइवेट प्रेक्टिस पर होता है। उन्हें अब बताना होगा कि कितने भर्ती हुए, कितने डिस्चार्ज, बेड की क्या स्थिति है? हाल में डीन ने सभी एचओडी को पत्र लिखकर इस तरह की जानकारी मांगी थी। चर्चा है कि डीन के कदम के बाद संचालनालय ने यह कदम उठाया है।

धमतरी निगम में बेंच खरीदी पर मचा बवाल

भाजपा ने बाजार से तीन गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी का लगाया आरोप, महापौर को घेरा

धमतरी। धमतरी नगर निगम में ताजा बवाल कास्ट आयरन बेंच की खरीदी को लेकर मचा हुआ है। विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि निगम ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार बाजार से तीन गुना ज्यादा कीमत पर कास्ट आयरन बेंच की खरीदी की है। यही नहीं इन बेंच को कबाड़ के साथ खुले में छोड़ दिया गया है। भाजपा ने मामले में महापौर को घेरते हुए खरीदी की जांच की मांग की है।

भाजपा पार्षद विजय मोटवारी ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि निगम ने 2022 से अब तक बगीचों में लगने वाले कास्ट आयरन बेंच की तीन बार खरीदी की है। महापौर की अनुशंसा पर 57 लाख रुपए की लागत से 340 नग बेंच खरीदे गए। इस तरह से एक बेंच करीबन पौने 17 हजार रुपए की पड़ रही है, जबकि खुले बाजार में ये बेंच 5 से 6 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं। इस तरह से बाजार की कीमत से तीन गुना ज्यादा कीमत पर निगम ने खरीदी की है।

यही नहीं इन बेंच को कबाड़

के बीच खुले में छोड़ दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब इन बेंच के इस्तेमाल कहां करना है, इसका पता नहीं था तो खरीदी क्यों की गई। वह भी एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार। निगम के सर्वेसर्वा होने के नाते महापौर विजय देवांगन ने खरीदी की अनुशंसा की है, लेकिन जब उन्हें नहीं मालूम कि इन बेंच का कहां इस्तेमाल होना है तो फिर उन्होंने खरीदी की अनुशंसा क्यों की।

भाजपा के आरोपों को महापौर विजय देवांगन राजनैतिक बताते हुए पल्ला झाड़ने का प्रयास करते नजर आए। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि कि कोई भी खरीदी महापौर नहीं, निगम प्रशासन करता है। महापौर सिर्फ अनुशंसा ही करता है। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं बेंच खरीदी की जांच कराने की चुनौती दी है। भाजपा और महापौर के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव की चल रही तैयारियों के बीच 20-25 दिन में आचार संहिता लगने की आशंका है। ऐसे में अगर बेंच खरीदी की मामला तूल पकड़ने लगा तो चुनाव के समय महापौर को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, जिसका खामियाजा आखिरकार कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है।

कड़ाके की ठंड से ठिठुरन शुरू, अलाव बन रहा सहारा

- उत्तर छत्तीसगढ़ में दो दिन शीतलहर की चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाओं का आगमन जारी है। इसके वजह से प्रदेश में कड़ाके कि ठंड पड़ रही है। इन दिनों रात और दिन दोनों के तापमान में गिरावट हुई है, जिसके वजह से रात के साथ अब दिन में भी ठंड का अहसास होने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई क्षेत्रों को लेकर शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद कोई विशेष परिवर्तन की संभावना

नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज और कल दो दिन शीतलहर रहने की संभावना है। वहीं आगामी दो दिनों तक मौसम में अभी कोई बदलाव नहीं होगा।

मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि प्रदेश के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड से ठिठुरन शुरू हो गया है। अब ओस की बूंदें जमकर बर्फ बदलने लगी है। हालांकि अब न्यूनतम तापमान में अब बदलाव नहीं होगा।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज होने के साथ ही शीतलहर चलने की संभावना जताई है। ऐसे में ठंड कंपकंपाने लगी है। रात के साथ ही अब दिन में भी ठंड लगने लगी है। लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को रायपुर में ठंड बढ़ी है। आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान नीचे गिरने से ठंड में बढ़ोतरी होगी।

ड्रोन से भेजी जाएगी दवाई और ब्लड सैंपल

तमनार। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवा और ब्लड सैंपल भेजने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्वास्थ्य सुविधाओं में ड्रोन तकनीक का उपयोग' के तहत आज ड्रोन के माध्यम से दवा एवं ब्लड सैंपल रायगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार भेजा गया। महज 15 मिनट में सफलतापूर्वक परीक्षण कर रिपोर्ट भेज दी गई।

रायगढ़ कलेक्टर निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. बीके चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में मिनी स्टेडियम रायगढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार हाईस्कूल मैदान तक ब्लड सैंपल और दवा भेजने का सफल ट्रायल किया गया। ड्रोन से वांछित स्थल तक दवा पहुंचाने के सफल ट्रायल से स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। बीएमओ डॉ. डीएस पैकरा ने बताया कि रायगढ़ से ड्रोन दवा लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार हाई स्कूल मैदान में सुरक्षित लैंडिंग की।

कार्यालय अस्पताल अधीक्षक एवं एकेडेमिक इंचार्ज
डी.के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर रायपुर (छ.ग.)
(वेबसाईट-www.pgiraipur.org ई-मेल dkspgi@gmail.com)

क्रमांक /5761/ डी.के.एस.रा./ स्था-1/2024 रायपुर, दिनांक 12/12/2024

-: रूचि की अभिव्यक्ति :-

दाऊ कल्याण सिंह स्नाकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र रायपुर छ.ग. के MICU वार्ड में स्थापित 01 नग UPS मशीन के लिए बैटरी को क्रय/विक्रय किया जाना है। चिकित्सालय में स्थापित बैटरी को क्रय / विक्रय का दर प्रस्तुत करने हेतु कार्यालीन समय सुबह 10:30 से सायं 5:00 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। UPS मशीन के लिए बैटरी को क्रय/विक्रय करने हेतु कार्यों के प्राक्कलन दर की सूचीं सीलबंद लिफाफों में अस्पताल अधीक्षक एवं ऐकेडमिक इंचार्ज, डी.के.एस.पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्युट एवं रिसर्च सेन्टर, रायपुर (छ0ग0) के नाम से दिनांक 26.12.2024 दोपहर 12.00 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम द्वारा पंजीकृति फर्मों से प्राक्कलन दर (कोटेशन) स्वीकार किया जावेगा। अधिक जानकारी के लिए के चिकित्सालय के वेब साईट www.dkspgi.in का अवलोकन करें।

प्राप्त प्राक्कलन दर (कोटेशन) को दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 1.00 बजे चिकित्सालय के क्रय समिति के द्वारा खोली जायेगी।

निविदा जमा करने की तिथि- 10.12.2024 से
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि- 26.12.2024 दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान- कार्यालय अस्पताल अधीक्षक एवं एकेडेमिक इंचार्ज डी.के.एस. सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय रायपुर (छ.ग.)
निविदा खोलने का स्थान- अस्पताल अधीक्षक डी. के. एस. सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय रायपुर के कक्ष में।

अस्पताल अधीक्षक
डी.के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, रायपुर (छ.ग.)
जी-242504541/3

प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के लिए आबंटन-आरक्षण की कार्रवाई 17 को

गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य, तीनों जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य और पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार आबंटन-आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी।

कलेक्टर द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार जिला पंचायत के सदस्य एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु श्री दिलेराम डाहिरे

परियोजना निदेशक जिला पंचायत (डीआरडीए) को नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत गौरेला के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई जनपद सभा कक्ष गौरेला में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु श्री अमित बेक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को नियुक्त किया गया है।

जनपद पंचायत पेण्ड्रा के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई सभा कक्ष जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पेण्ड्रा में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु श्री अविनाश कुजूर तहसीलदार पेण्ड्रा को नियुक्त किया गया है।

जनपद पंचायत मरवाही के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई सद्भावना भवन मरवाही में होगी। आरक्षण की कार्रवाई हेतु श्री प्रफुल्ल रजक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही को नियुक्त किया गया है। सभी स्थानों पर आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर कार्यवाही समाप्ती तक चलेगा।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कांकेर मण्डल, कांकेर
Email - sepwdkanker.2010@rediffmail.com/se.kanker@nic.in, Fax No. 07868-224040

-: ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना :-

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित सप्लाई / सड़क कार्य हेतु दिनॉक 24.12.2024 समय 17:30 बजे तक ऑनलाईन (Online) निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	एन.आई.टी. नंबर	टेण्डर नंबर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3	4	5
01	110	162633	उप-संभाग केशकाल के अंतर्गत विभिन्न आकार के गिट्टी (crushed stone) & dust का सप्लाई (आपूर्ति) का कार्य।	10.00 लाख
02	111	162634	उप-संभाग क्र . 01 कोण्डागांव के अंतर्गत विभिन्न आकार के गिट्टी, मुरूम एवं रेत सप्लाई (आपूर्ति) का कार्य।	10.00 लाख
03	112	162635	उप-संभाग क्र. 02 कोण्डागांव के अंतर्गत विभिन्न पुल पुलिया में कि.मी. स्टोन, पेंटिंग, फिंगरिंग एवं नंबरिंग कार्य तथा विभिन्न मार्गों में पेंटिंग, फिगरिंग एवं साईन बोर्ड कार्य।	10.00 लाख
04	113	162636	पखांजूर अनुविभाग के विभिन्न मार्गों पर 5ह्रद्ध कि.मी. स्टोन, 0.20 कि.मी. स्टोन सांकेतिक बोर्ड कार्य।	9.77 लाख
05	114	162638	उपसंभाग क्र. 01 नारायणपुर अंतर्गत पेटी बाजार सप्लाई का कार्य।	10.00 लाख
06	115	162639	उपसंभाग नरहरपुर अंतर्गत पेटी बाजार सप्लाई का कार्य।	10.00 लाख
07	116	162640	उपसंभाग चारामा अंतर्गत पेटी बाजार सप्लाई का कार्य।	10.00 लाख
08	117	162712	उपसंभाग केशकाल के अंतर्गत 01 नग मुख्य जिला मार्ग एवं 04 नग ग्रामीण मार्गों में डब्ल्यू.एम. एम एव बी.टी. पेंच मरम्मत कार्य ।	79.93 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट बेव पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय बेवसाईट https://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है। डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 24.12.2024 है।
ठेकेदार का हॉट मिक्स प्लांट होना अनिवार्य है। (स.क्र.08 के लिए)
नोट:- द्वितीय आमंत्रण (स.क्र. 01 से 07) एवं चतुर्थ आमंत्रण (स.क्र. 08)
टीप:- 1. निविदा क्र. 162638, 162639 एवं 162640 कार्य हेतु संबंधित कार्यक्षेत्र के नगर पंचायत/पालिका का वैध गुमास्ता प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं नगर पंचायत/पालिका की परिधि में दुकान/फर्म का होना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, कांकेर मण्डल, कांकेर
जी-242504507/7

संसद का गतिरोध कैसे खत्म हो

रजनीश कपूर

संसद का शीतकालीन सत्र पहले दिन से हंगामेदार बना हुआ है। विपक्ष ने सरकार को अडानी मुद्दे पर घेर रखा है। विपक्ष की मांग है कि सरकार अडानी मुद्दे पर बयान देकर अपना रुख साफ करे। परंतु जैसे ही विपक्ष अडानी मुद्दे को उठाता है तो हल्ला मच जाने के कारण संसद के सत्र को स्थगित करना पड़ता है। इसके साथ ही राज्यसभा में भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि जब भी विपक्ष सरकार को भ्रष्टाचार या अन्य किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है तो संसद का वह सत्र शोर-शराबे के बीच बर्बाद हो जाता है। वैसे तो हर सरकार ही ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहती, जहां उसकी छीछालेदर हो। वह उससे बचने के रास्ते खोजती है। यदि सरकार का दामन साफ है और वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है तो उसे ऐसे किसी मुद्दे का सामना करने से हिचकना नहीं चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहा। विपक्षी दलों का आरोप है कि जब भी सरकार के पास उनके सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होता तो वे संसद को ठप्प कर देती है पर इसके लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराती है। भ्रष्टाचार की बात करें तो दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार के सूचकांक को जारी करने वाली संस्था 'ट्रांसपेरैंसी इंटरनैशनल' की एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत का 28 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का धन अवैध रूप से विदेशों में जमा है। ऐसी ठोस और विश्वसनीय रिपोर्ट के बाद किसी भी सरकार को हरकत में आना चाहिए था और इस एजैंसी व ऐसी अन्य एजैंसियों की मदद से इस रिपोर्ट के आधार ड्क्षबदुओं की जांच करनी चाहिए थी जिससे भ्रष्टाचार की जड़ पर कुठाराघात किया जा सकता। पर सरकार किसी भी दल की क्यों न रही हो जब-जब उससे इस बाबत पूछा गया कि उसने इस रिपोर्ट को लेकर तथ्य जानने की क्या कोशिश की, तो सरकार का उत्तर था, चूंकि 'ट्रांसपेरैंसी इंटरनैशनल' नाम की संस्था भारत सरकार का अंग नहीं है, इसलिए उसकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। यहां 2011 की एक घटना को याद करना उचित होगा। जब सत्तापक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में जोर-शोर से घेरने वाली भाजपा को ही मीडिया ने घेर लिया था। मीडिया का सवाल था कि सत्तापक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की मांग करने वाली भाजपा अपनी कर्नाटक सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के घोटालों के विषय में चुप क्यों है? ऐसे में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 'येदियुरप्पा ने जो कुछ किया, वह अनैतिक है पर अवैध नहीं।' अब इस बयान को पढ़कर कौन ऐसा होगा जो अपना सिर न धुने। यानी कि क्या भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व सार्वजनिक जीवन में अनैतिक आचरण को स्वीकार्य मान रहा था? यही वजह है कि उस समय की भाजपा की कथनी और करनी में भ्रष्टाचार से लड़ने और उसे समाप्त करने की कोई मंशा दिखाई नहीं दी। सारा शोर राजनीतिक लाभ उठाने को मचाया गया। जनता को यह संदेश दिया गया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के विरूद्ध है, जबकि हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ भाजपा नेतृत्व भ्रष्टाचार से लड़ना ही नहीं चाहता था। इसलिए उस समय का विपक्ष जे.पी.सी. की मांग पर अड़ा हुआ था। जिसका कोई हल निकलने वाला नहीं था और उस समय का गतिरोध यूं ही चलता रहा। न सिर्फ भ्रष्टाचार व अन्य मामलों को लेकर सरकार पर, बल्कि चुनाव आयोग पर भी चुनावों की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। चुनावों के बाद सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न बने। चुनावों का आयोजन करने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था केंद्रीय चुनाव आयोग को हर चुनावों को पारदर्शिता से कराना चाहिए। यह बात बीते कई महीनों से सभी विपक्षी दल और अन्य जागरूक नागरिक कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हर दल को पूरा मौका दिया जाए और निर्णय देश की जनता के हाथों में छोड़ दिया जाए। बीते कुछ समय से चुनाव आयोग पर, पहले ई.वी.एम. को लेकर और फिर वी.वी. पैट को लेकर और चुनावी आंकड़ों को लेकर काफी विवाद चल रहा है। हर विपक्षी दल ने एक सुर में यह आवाज लगाई कि देश से ई.वी.एम. को हटा कर बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराया जाए। परंतु देश की शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए अधिक सावधानी बरतने को कहा और ई.वी.एम. को जारी रखा। 'इंडिया' गठबंधन अगर सोचता है कि वह देश में अडानी मुद्दे और ई.वी.एम. के मुद्दों पर 'बोफोर्स' जैसा माहौल बना लेगा, तो यह सम्भव नहीं लगता क्योंकि बोफोर्स के समय नेतृत्व देने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसी साफ छवि वाला नेता मौजूद था और आज के राजनेताओं में ऐसा एक भी चेहरा नहीं जिसे देश की जनता बेदाग मानती हो।

विपक्ष की रार से कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को होगा नुकसान

कमलेश पांडे

कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के सवाल पर जो मौजूदा चिल्ल-पों मची हुई है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे न तो तृणमूल कांग्रेस नेत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक भला होने वाला है और न ही उनकी सुर में सुर मिलाने वाले एनसीपी शरद पवार के शरद पवार-सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे-आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव-रामगोपाल यादव या आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल आदि जैसे नेताओं का। हां, इससे कांग्रेस आई की उस सियासी साख को धक्का अवश्य लगेगा, जो कि बमुश्किल उसने राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हासिल कर पाई है।

राजनीतिक मामलों के जानकारों का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा की हार जरूर मायने रखती है, क्योंकि यह जीती हुई बाजी हारने के जैसा है। लेकिन सिर्फ इसको लेकर ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस से छीन लेना कोई राजनीतिक बुद्धिमानी का काम प्रतीत नहीं होता है। शायद कांग्रेस भी इसे नहीं मानेगी और किसी भी राष्ट्रीय दल को क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने भी नहीं टेकने चाहिए, यदि सत्ता प्राप्ति के लिए संख्या बल का खेल नहीं हो तो! बीजेपी भी यही करती है और अपने गठबंधन सहयोगियों को उनकी वाजिब औकात में रखती है। तीसरे-चौथे मोर्चे की विफलता के पीछे भी तो अनुशासनहीनता या अतिशय महत्वाकांक्षा का खेल ही तो था, जिसे बहुधा राजनीतिक रोग समझा जाता है।

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद तुरंत कहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपने अहंकार को अलग रखना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वह इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने यहां तक कहा कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए भी विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चा का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वे इसे नहीं चला सकते, तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। वहीं, यह पूछे जाने पर कि एक मजबूत भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख के बावजूद वह इंडिया ब्लॉक की कमान क्यों नहीं संभाल रही हैं? तो इस पर बनर्जी ने कहा, अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। उन्होंने कहा, मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूं। बता दें कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गठित इंडिया ब्लॉक में दो दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हैं। हालांकि, आंतरिक मतभेदों और आपसी तालमेल की कमी की वजह से इसकी कई बार आलोचना भी होती रही है। इसी वजह से इसके प्रमुख सूत्रधार रहे जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया और भाजपा के खेमे में चले गए। वो भी इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद पाना चाहते थे, जो लालू प्रसाद के परोक्ष विरोध के चलते सम्भव नहीं हो पाया। ऐसे में संभव है कि ममता भी एकबार फिर से तीसरे मोर्चे को मजबूत करने की पहल करें और नीतीश की तरह ही इंडिया गठबंधन को टा-टा, बाय-बाय कर दें।

उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी का यह बयान उनकी पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कांग्रेस और अन्य इंडिया ब्लॉक सहयोगियों को लेकर दिए बयान के बाद सामने आया है। तब कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपने अहंकार को अलग रखना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में मान्यता देनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने जहां महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड संख्या में सीटें हासिल कीं तो वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक ने सिर्फ झारखंड में जेएमएम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मजबूत वापसी की। कहने का तातपर्य यह है कि कांग्रेस ने अपनी हार का सिलसिला जारी रखा और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम के जूनियर पार्टनर के रूप में सामने आई और विपक्षी ब्लॉक में इसकी भूमिका और भी कम हो गई क्योंकि अन्य सहयोगियों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया।

वहीं, दूसरी ओर हाल ही में हुए उपचुनावों में भाजपा को हराकर टीएमसी की जीत ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभुत्व को मजबूत किया है, जबकि विपक्षी अभियान आरजी कर मेडिकल कॉलेज विरोध जैसे विवादों पर केंद्रित थे। सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे, उसके सहयोगी सीपीआई (एमएल) लिबरेशन और कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के सहयोगी हैं, सभी को बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जबकि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे अक्सर गठबंधन का वास्तविक नेता माना जाता है। यही वजह है कि टीएमसी ने लगातार ममता बनर्जी को गठबंधन की बागडोर संभालने की वकालत की है।

यह ठीक है कि तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा को सियासी चोट पहुंचा रही हैं और सदैव उस पर भारी प्रतीत हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह राष्ट्रीय नेत्री बन गईं और उनका चेहरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चेहरे से ज्यादा सर्वस्वीकार्य हो गया, वो भी अखिल भारतीय स्तर पर? चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शरद पवार के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार हों या उनकी सियासी वारिस सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों या उनके राजनीतिक वारिस आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव या आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या उन जैसे इंडिया गठबंधन के कोई अन्य नेतागण, किसी का चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर उतना सर्वस्वीकार्य नहीं हो सकता है जितना कि राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। इसलिए समकालीन बयानबाजी से इंडिया गठबंधन और उसमें शामिल सभी दलों को ही क्षति होगी, यह उन्हें समझना होगा।

वैसे भी भारतीय मतदाताओं के बीच कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन, राजद-सपा-झामुमो नीत महागठबंधन, शिवसेना यूबीटी-एनसीपी शरद पवार नीत महाविकास अघाड़ी के अलावा तीसरे या चौथे मोर्चे में शामिल रहे क्षेत्रीय दलों की साख अच्छी नहीं है। जनता पार्टी, जनता दल और संयुक्त मोर्चे की कई गठबंधन सरकारों को असमय गिराने का आरोप जहां कांग्रेस पर लगता आया है, वहीं तीसरे मोर्चे और चौथे मोर्चे के बारे में तो राजनीतिक अवधारणा यही है कि इन्हें केंद्र में सरकार चलाना ही नहीं आता और इसमें शामिल दल भले ही अपने-अपने राज्यों में सफल रहे हों, लेकिन सुशासन स्थापित करने और भ्रष्टाचार रोकने में अकसर विफल रहे हैं, जिससे ब्रेक के बाद मतदाता इन्हें खारिज कर देते हैं। इनकी इसी कमजोरी का राजनीतिक फायदा भाजपा को मिला, जबकि ये लोग उसे राजनीतिक अछूत तक करार दे चुके हैं।

बता दें कि 1990 के दशक में कोई भी दल पहले भाजपा से गठबंधन करने से सिर्फ इसलिए डरता था कि कहीं उसका मुस्लिम वोट छिटक न जाए। लेकिन अपने राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के अग्रगामी विचारों के साथ-साथ बीजेपी ने सुशासन, विकास और गठबंधन सरकार चलाने की योग्यता को साबित करके भारतीय मतदाताओं का दिल एक नहीं, बल्कि कई बार जीत लिया और कांग्रेस के अधिकांश पुराने सियासी रिकॉर्ड को मोदी 3.0 सरकार ने ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद उसकी लोकप्रियता एक बार फिर से उफान पर है।

वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस-सपा गठजोड़ से उसे जो धक्का लगा, उसकी भरपाई उसने हरियाणा-महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा ने आरएसएस की उपेक्षा की कीमत चुकाई थी, अन्यथा आज वह अपने गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन अब उसके इशारे पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में अंतर्कलह मची हुई है, उससे आम चुनाव 2029 में भी उसका निष्कंटक राज बरकरार रहने के आसार हैं। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे चली जाएगी, जिसकी भरपाई वो शायद ही कभी कर पाए।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

क्योंकि पुराण तो वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, और गाणपत्य आदि पांचों सम्प्रदायों की अधिकारीभेद से वैज्ञानिक व्यवस्था बैठाते हैं। उनमें किसी सम्प्रदाय की निन्दा का क्या प्रयोजन? अतएव पं. ज्वालाप्रसाद जी मिश्र आदि समालोचकों ने हस्तलिखित प्रतियों में न होने के कारण उक्त श्लोक को प्रक्षिप्त माना है यही इसका उत्तर है।

कदाचित् प्रतिवादी इस समाधान को पर्याप्त न समझे और इसे मूल पुराण का पाठ कहने के लिए हो आग्रह बांध बैठे, तब भी इसके अस्तित्व से पुराणों के व्यास-कर्तृत्व में कोई बाधा नहीं पहुँच सकती, क्योंकि शास्त्र की दृष्टि में सभी सम्प्रदाय वेदोक्त एवं अनादि हैं। आद्यशङ्कराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य आदि महानुभाव किसी अभिनव सम्प्रदाय के प्रवर्तक नहीं हुए, बल्कि वेदोक्त किन्तु समय-चक्र की वक्र गति से विलुप्तप्राय: तत्तत्सम्प्रदाय के पुनरुद्धारक ही हुवे हैं।

जिस शङ्ख-चक्र-विधान को स्वामी रामानुज जी से सम्बद्ध कहा जा रहा है, उसको पवित्रं ते विततम् (ऋग्वेद 6 ।83 ।1-2) आदि वेदादि अनादि ग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा वैष्णवधर्मरत्नाकर प्रभृति पुस्तकों में वेदमूलक सिद्ध किया गया है। ऐसी दशा में वेदव्यास जी ने उसी अनादिसिद्ध शङ्ख-चक्र-विधान को लक्ष्य करके शैवदीक्षादीक्षित अधिकारियों के लिए उसका निषेध किया है यह भी सुसम्भव है।

यदि प्रतिवादी लिङ्गपुराणोक्त शङ्ख-चक्रों के खण्डन को तथा पद्मपुराणोक्त शङ्ख-चक्रों के विधान को उपस्थित करके परस्पर विरुद्धता का आक्षेप करना चाहेगा और इससे इन दोनों पुराणों को व्यास जी के बजाये किन्हीं अन्य कर्ताओं की कृति बनाने का यत्न करेगा तो वेदों पर यही आक्षेप लागू हो जायेगा।

क्रमशः ...

'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस'

हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध ऊर्जा दक्षता ब्यूरो करता है। ज्ञात हो, इस ब्यूरो ने वर्ष 2001 में देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था।

दुनियाभर में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और उसी के अनुरूप ऊर्जा की खपत भी निरन्तर बढ़ रही है। दूसरी ओर जिस तेजी से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उससे भविष्य में परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के नष्ट होने की आशंका बढ़ने लगी है। अगर ऐसा होता है तो मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाएगा।

यही कारण है कि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्त्रोतों को बचाने के लिए विश्व भर में ऊर्जा संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देते हुए इसके प्रतिस्थापन के लिए अन्य संसाधनों को विकसित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

ऊर्जा के अपव्यय को कम करने, ऊर्जा बचाने और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष एक खास विषय के साथ कुछ लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मनाया जाता है।

वास्तव में इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को न्यूनतम करते हुए लोगों को मानवता के सुखद भविष्य के लिए ऊर्जा की बचत के लिए प्रेरित करना ही है। इसी क्रम में विद्युत मंत्रालय द्वारा देश में ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान शुरू किया गया। यह एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान बन गया है।

देश में ऊर्जा संरक्षण तथा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1977 में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन किया गया था। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2002 में एक अन्य संगठन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्थापित किया गया। ब्यूरो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने घर अथवा कार्यालय में लाइट, पंखे, हीटर, कूलर, एसी तथा बिजली के अन्य किसी भी उपकरण के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण करते हुए ऊर्जा की बचत कर सकता है। इस संबंध में लेखक और स्वतंत्र टिप्पणीकार योगेश कुमार गोयल अपनी पुस्तक प्रदूषण मुक्त सांसें में बताते हैं, मैंने विस्तार से उल्लेख किया है कि किस प्रकार छोटे-छोटे स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए कदम उठाकर भी प्रत्येक नागरिक देश के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान में बहुत बड़ी मदद दे सकता है और इस प्रकार बड़ी मात्रा में ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। अगर ऐसे ही कुछ छोटे उपायों का उल्लेख किया जाए तो पुराने बल्बों के स्थान पर सीएफएल या एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाए। आई.एस.आई. चिह्नित विद्युत उपकरणों का ही उपयोग करें। यथासंभव दिन के समय सूर्य की रोशनी का अधिकतम उपयोग किया जाए और जरूरत न होने पर लाइटें, पंखे, कूलर, एसी, हीटर, गीजर इत्यादि विद्युत उपकरण बंद रखें।

यूनुस के शासन में आखिर कहां जा रहा है पड़ोसी मुल्क?

अमिय भूषण

नस्लीय बर्बरता और हिंसा की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बने बांग्लादेश में भारतीय विदेश सचिव के दौरे के बाद आशंकाओं का बादल अब और भी साफ होने चला है। कहना गलत नहीं होगा कि वो जो कातिल है वही निज़ाम वही मुंसिफ है वो क्या ख़ाक हिन्दू अल्पसंख्यकों के हक़ में फैसला लेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी की यात्रा के परिणामो के लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे ठीक वैसा ही फलाफल निकल कर सामने आया है।

दरअसल, बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्य हिन्दू उत्पीड़न पर भारतीय विदेश सचिव की बेलाग और वाज़िब बयान पर अंतरिम सरकार के निज़ाम यूनुस और उनके प्रशासन ने इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला भर कहकर अपनी मंशा और योजना दोनों जाहिर कर दी है। इसी बीच मज़हबी कट्टरपंथी बांग्लादेशी नेताओं के बड़बोलेपन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तल्ख़ पलटवार किया है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस और उनके शासन को फासीवादी करार देते हुए बांग्लादेशी कानून के मुताबिक निज़ाम और उनके सरपरस्तों का हिसाब करने की कसम उठाई है।

सत्ता के संरक्षण में सम्पूर्ण बांग्लादेश में हिन्दू नरसंहार की वीभत्स योजना पर काम कर रहे कार्यवाह प्रधानमंत्री यूनुस के नोबल पुरस्कार के खिलाफ भी नागरिक समूहों ने नोबेल कमेटी के सामने आपत्ति खड़े किए हैं। इन सभी घटनाक्रमों के बीच बांग्लादेश खबरों की सुर्खियों का हिस्सा है। इन चर्चाओं मे सबसे बड़ी चर्चा फिलहाल वहां के अल्पसंख्यक हिंदू विरोधी चरित्र को लेकर है। ऐसा भी नही है कि यहां ये सब कोई पहली बार हो रहा है। दरअसल, अतीत में भी यहां के हिंदू समुदाय को यह सब झेलना पड़ा है, लेकिन पांच अगस्त 2024 के बाद से हालात कहीं बुरे है। इस दिन यहां एक अप्रत्याशित मगर सुनियोजित घटना उपरांत निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था तब से बांग्लादेश की बागडोर उन हाथों में है जिनका विश्वास लोकतंत्र एवं मानवाधिकार मे कतई नहीं है और जिसका प्रमाण सत्ता प्रायोजित अनवरत् जारी हिंसा और दमन है।

बात तत्कालीन घटना की करें तो यह एक हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास के गिरफ्तारी से संबंधित है। पहले इन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप मे फिर इनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। यहां तक कि जेल में इन साधुओं को बाहर से भोजन उपलब्ध कराने के नाते भी गिरफ्तारियां हुई है, क्योंकि अपने भोजन संबंधित नियमों के नाते ये कुछ भी और कही का भी खाना नहीं खा सकते हैं। इस नाते कई दिन बिना भोजन के भी इन लोगों ने गुजारा है।

बात इनके आंदोलन की करें तो धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा का शिकार हिंदू समुदाय अपने एक आठ सूत्री मांग के साथ देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान पूरे बांग्लादेश में शांतिपूर्ण सभाओं का दौर जारी था। इसी का चेहरा गौड़ीय वैष्णव परंपरा से संबद्ध संस्था इस्कॉन के चटगांव आश्रम प्रमुख साधु चिन्मय प्रभु थे। ऐसे में बजाय अराजक तत्वों पर अंकुश की जगह शासन ने विरोध के स्वर को कुचलने के लिए ये बर्बर कार्यवाही की है।

इधर, रहा सवाल आरोपों का तो ये मसला न्यायालय के विचार का है, लेकन जिस प्रकार से इसे अनावश्यक तूल दिया गया है वो बेहद खतरनाक है। पूरे देश में हिंदू विरोधी हिंसा का माहौल है। इसी क्रम में एक अप्रत्याशित दुखांत घटना भी घटी है। विरोध प्रदर्शनों के बीच एक मुस्लिम वकील की हत्या हो गई, जिसके उपरांत हिंदू उत्पीड़न का सिलसिला सा पुनः चल पड़ा है और जिसकी परिणति चिन्मय प्रभु के पक्षकार अधिवक्ता के ऊपर आत्मघाती हमला है जिसके उपरांत वो अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं।

यही नही मुस्लिम अधिवक्ता हत्या मे बिला वजह 70 हिंदू वकीलों को आरोपी बनाया गया है। इस नाते भय के कारण कोई भी वकील इनके लिए न्यायालय में खड़े होने को तैयार नहीं हैं। न्यायालय पर मतांध शासन और मजहबी भीड़ दोनों का दबाब है। इस नाते सुनवाई अब जनवरी मे होनी है। यहां न्याय की मांग कर रहे हिंदुओं पर मतांध मुस्लिम भीड़ का टूट पड़ना अब सामान्य बात है। जबकि आपत्ति व्यक्त करने पर प्रशासन उलटे इन्हीं के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है।

बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम को चटग्राम के हिंदू व्यवसायियों संग पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से समझा जा सकता है। भय के नाते यहां लोगों ने पुलिस मे मामला तक दर्ज नहीं कराया। इस बीच इस्कॉन जैसे विशुद्ध सेवाभावी अंतराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था भी इनके निशाने पर है। इसे आतंकी संगठन घोषित करने हेतु प्रचार चलाया जा रहा है।यहां तक की न्यायालय पर अनुचित दबाब तक बनाया जा रहा है। जबकि ये संस्था भेदभाव से रहित निस्वार्थ सेवा और परोपकारी कार्यो के लिए जानी जाती है। ये लोग विभिन्न आपदाओं मे बढ़ चढ़कर राहत कार्यो चलाते रहे हैं। इसके उलट हिंदू युवतियों से दुर्व्यवहार और बलात्कार करने तथा हिंदू परिवार एवं मंदिरों पर हमला करने वालो पर कोई रोक-टोक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन इस संगठित एवं सुनियोजित अपराध से अवगत् नहीं है। इन्हीं प्रवृतियों के नाते यहां इन दिनों अवयस्क हिंदू लड़कों पर ईशनिंदा के अनुचित आरोप जड़े जा रहे हैं, जिसकी परिणति हर बार जिहादी भीड़ द्वारा पुलिस बल के सामने इनकी नृशंस हत्या के रूप में घटनाएं सामने आ रही है।

दुनियाभर से इस बर्बर पाशविक कृत्य के विरोध में स्वर भी उठ रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग से लेकर ब्रिटिश संसद और संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल तक पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी धुर विरोधी पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है।

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का यह पुत्र फिलहाल लंदन मे है। अपने भारत विरोधी विचार और बांग्लादेश के अतिवादी संगठन जमात से निकटता के बावजूद इन्होंने कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये सरकार नहीं चलेगी। जबकि भारत मे निर्वासन काट रही शेख हसीना ने इसके लिए सीधे तौर पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। बात पड़ोसी देश भारत की करें तो उसके लिए वाकई यह चिंतापूर्ण स्थिति है। बांग्लादेश संग भारत की सीमा करीब चार हजार छियानवे किलोमीटर लंबी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नदी पहाड़ एवं जंगल के नाते दुर्गम है। इसलिए यहां सीमा पर गश्त एवं सुरक्षा कही मुश्किल है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर अतिवादी इस्लाम का उभार पूरे इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है।

यही नहीं एक अराजक सरकार का होना और भारत विरोधी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए परेशानियों का सबब है। यह भारत के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संग विकास के लिए भी एक गंभीर खतरा है।

आज का इतिहास

1896 ग्लासगो सबवे तीसरा सबसे पुराना भूमिगत मेट्रो दुनिया खोला गया।

1900 जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने अपने ब्लैक-बॉडी रेडिएशन कानून की एक आनुवांशिक व्युत्पत्ति प्रस्तुत की, जिसमें सुझाव दिया गया कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा केवल मात्रात्मक रूप में उत्सर्जित की जा सकती है।

1911 नॉर्वे के खोजकर्ता रोअल्ड एमन्डसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।

1911 नार्वे के खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसेन और उनकी टीम दक्षिण ध्रुव (चित्र) तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।

1913 कोंगो-क्लास का चौथा और आखिरी जहाज, हारुना, लॉन्च किया गया था, जो अंतत: द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कार्यक्षेत्रों में से एक बन गया।

1918 ब्रिटेन की महिलाओं ने पहली बार आम चुनावों में मतदान किया।

1918 हेस के प्रिंस फ्रेडरिक चार्ल्स ने फिनिश सिंहासन से त्यागपत्र दिया।

1960 ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इयान मेकिफ को रन आउट किया गया, जिससे क्रिकेट के इतिहास में पहला टेस्ट हुआ।

1962 नासा का मेरिनर 2 दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया, जो शुक्र से उड़ान भरते समय एक असफलता का सामना करता है।

1963 लॉस एंजिल्स में बाल्डविन हिल्स जलाशय को बांधने वाला बांध, 277 घरों को नष्ट करने वाली बाढ़ जारी करता है।

1983 जनरल एच.एम. इरशाद ने खुद को बंगलादेश का राष्ट्रपति घोषित किया।

1994 तीन घाटियों के बांध का निर्माण यांग्त्ज़ी रिवरिन चीन पर शुरू हुआ।

1995 बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं ने पेरिस में डेटन संधि पर दस्तखत कर साढ़े तीन साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया था।

1995 पेरिस में डेटन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

1998 इराक पर निरस्त्रीकरण संकट: अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इराक पर हवाई हमले का आदेश दिया यूएनएससीओएम इराक से सभी हथियार निरीक्षकों को वापस लिया गया।

24 वर्षों से विकास के नव आयाम स्थापित कर रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा

डॉ. रमन सिंह

. 01 नवम्बर 2000 का दिन जब केवल भारत के मानचित्र पर कुछ नई रेखाएं नहीं खिंची थी बल्कि डॉ. खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्री हरि ठाकुर, श्री केयूर भूषण, श्री केशव सिंह ठाकुर और श्री चंदूलाल चंद्राकर जैसे महापुरुषों के दशकों के प्रयास का प्रतिफल रहा कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा में सर्वप्रथम श्री महेश तिवारी (सदस्य जनता पार्टी) द्वारा 28 जून सन् 1991 को मध्यप्रदेश राज्य को तीन पृथक प्रदेशों में विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हेतु केन्द्र से अनुरोध किये जाने हेतु प्रस्तुत अशासकीय संकल्प अस्वीकृत हो गया। इसके बाद इसके बाद श्री गोपाल परमार ने 18 मार्च 1994 को एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया- सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के विस्तृत क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक परंपराएँ, कानून व्यवस्था तथा जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अलग कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाये जाने की शासन आवश्यक पहल करें। इस पर तीन घंटे की चर्चा उपरांत संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ। फिर 15 अप्रैल 1998 को मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन मंत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने मध्यप्रदेश विधान सभा में 15 अप्रैल 1998 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के निर्णय पर भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किये जाने का शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो पारित हुई।

मुझे आज भी श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी का सप्रेशाला मैदान, रायपुर की सभा में वो उद्बोधन याद है, जहाँ उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा था कि आप मुझे 11 सांसद दो और मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। वर्ष 1998 में बारहवीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में भी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति संकल्प लिया गया था और इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में 31 जुलाई 2000 तथा राज्यसभा में भी 09 अगस्त 2000 को पारित हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत 01 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश से पृथक होकर देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान और छत्तीसगढ़वासियों को आकांक्षाओं को सम्मान मिला।

आजादी के पूर्व से छत्तीसगढ़ प्रान्त के संसदीय ज्ञान और लोकप्रिय नेताओं का सदन में रहा है प्रतिनिधित्व

छत्तीसगढ़ को भले ही भारत के नक्शे में पहचान सन 2000 में मिली लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आज़ादी के पूर्व से सीपी एंड बरार में दिखाई देता रहा, जब पहली बार 31 अप्रैल 1937 को दुर्ग के संजारी बालोद से चुनाव जीतकर घनश्याम सिंह गुप्त जी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। श्री गुप्त जी लगातार 3 बार (1937-1952) 15 वर्षों तक विधानसभा अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे।

इसके साथ ही जब 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की भाषा आवश्यक रूप से अंग्रेजी थी तब श्री गुप्त जी ने 1937 में विधानसभा की भाषा हिंदी और मराठी कर दीए अपनी मातृभाषा के प्रति तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह गुप्त जी का समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रेम ही थाए जिसकी वजह से वह न केवल संविधान सभा के सदस्य बने बल्कि विधानसभा के द्वारा उन्हें संविधान के हिंदी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। डॉ राजेंद्र प्रसाद जी की इच्छा के अनुरु उन्होंने 2 वर्ष 6 माह के अंतर्गत भारतीय संविधान का हिंदी ड्राफ्ट प्रस्तुत किया।

सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के सदन में छत्तीसगढ़ प्रान्त के दिग्गज नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। यह अद्भुत संयोग था कि छत्तीसगढ़ अंचल के श्री रविशंकर सदन के नेता (मुख्यमंत्री) के रूप में थे। छत्तीसगढ़ अंचल के ठाकुर प्यारेलाल सिंह मध्यप्रदेश विधान सभा के नेता.प्रतिपक्ष और उसी समय श्री घनश्याम सिंह गुप्त जी विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी पर थे। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसी अंचल के दुर्ग से श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, श्री श्यामाचरण शुक्ल भी रहे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ अंचल के श्री मोतीलाल वोरा दो बार मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हुए। वर्ष 1985-90 में छत्तीसगढ़ के स्वण् श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे।

लेकिन यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर क्यों एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की आवश्यकता पड़ी जब छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व इतना मजबूत था और छत्तीसगढ़ के नेताओं का इतना प्रभाव था तब क्यों इस प्रदेश के लोगों के मन में एक पृथक राज्य की भावना थी। इसके लिए जब हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं तब संयुक्त मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र खनिज और अन्य संपदाओं से भरपूर होने के उपरांत भी वंचित और उपेक्षित नजर आता हैए क्योंकि भोपाल स्थित विधानसभा तक हमारे क्षेत्र की आवाज को पहुंचाना और जनकल्याणकारी योजनाओं से इस अंचल को जोड़ना बहुत कठिन था। यह एक ऐसा दौर था जब हम अगर कवर्धा के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा से 5 लाख रुपए की सड़क भी स्वीकृत करवा लाते थे तब वह एक बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सिर्फ एक नए राज्य का निर्माण नहीं था बल्कि सुकमा से सरगुजा तक निवासरत इस पूरे क्षेत्र के लोगों को नई आवाज़ देने और उनके अधिकारों को प्राथमिकता के साथ उठाने के लिए एक पृथक पटल भी उपलब्ध किया गया।

14 दिसम्बर सन 2000 को नए छत्तीसगढ़ में

जन.जन की आवाज को एक मंच प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना हुई, छत्तीसगढ़ गठन के समय विधानसभा के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां थी। उपयुक्त भवन, संसाधनों की कमी एवं संसदीय विद्या के पारंगत अनुभवियों की कमी के बावजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम चार दिवसीय ऐतिहासिक सत्र 14 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2000 तक रायपुर स्थित राजकुमार कालेज के जशपुर हॉल में अस्थायी तौर पर निर्मित सभा भवन में संपन्न हुआ। इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ विधानसभा को रायपुर बलौदाबाजार मार्ग पर बरोंदा गांव स्थित भारत.सरकार के जल.ग्रहण मिशन संस्थान के लिए बने नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किया गया और जहाँ आज दिनांक तक संचालित है।

जब छत्तीसगढ़ को अपना पृथक राज्य और पृथक विधानसभा मिली तब अन्त्योदय की विचारधारा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के कल्याण और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए हमारी विधानसभा ने ऐतिहासिक निर्णय लिए। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ की छवि एक पिछड़े और वंचित प्रदेश की थी। भूख से लोगों की मौत हो जाना और सीमित अवसरों की वजह से लोगों के छत्तीसगढ़ से बाहर कूच करने ने प्रदेश की छवि एक पलायन करने वाले राज्य की बना दी थी। जिसे परिवर्तित करने में हमारी विधानसभा ने ऐसे कानून बनाये जो इतिहास के सदैव के लिए अंकित हो गए। जब हमारी विधानसभा ने खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत 1 रूपये किलो चावल की योजना को 21 दिसम्बर 2012 सदन में पारित किया तब श्भोजन का अधिकारश् देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना। हमारी इस व्यवस्था को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के लिए आदर्श बताया और पीडीएस की सराहना की। इसके साथ ही युवाओं को कौशल उन्नयन का कानूनी अधिकार देश में सबसे पहले 21 जुलाई 2013 को हमारी ही विधानसभा में पारित हुआ। हमारी विधानसभा ने लोककल्याण के साथ ही सांस्कृतिक उत्थान पर भी पूरा जोर दिया और 3 अगस्त 2010 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का विधेयक पारित कर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। हमारी विधायिका की अद्भुत शक्ति है जो न केवल प्रदेशवासियों के विकास को सुनिश्चित करती है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी संरक्षित रखकर एक बेहतर संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करती है। हमारी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने की एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। कोरोना काल को अपवाद के रूप में छोड़ दें तो हमारे सदन में बजट कभी गिलोटीन से पारित नहीं हुआ है। हमेशा ही छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सभी विभागों के प्रमुख विषयों पर चर्चा करने के बाद बजट को पटल पर रखा जाता है और उसके बाद ही बजट पारित होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक विशेष प्रक्रिया है हमारी विधानसभा में यदि कोई सदस्य सत्र के दौरान अपनी कुर्सी से उठकर वेल (गर्भगृह) में प्रवेश करता है तो वह स्वत: ही निलंबित हो जाता है और उसे सदन से बाहर जाना पड़ता है। यह हमारे लोकतंत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक पवित्र प्रक्रिया है जिसका पालन सभी दल करते हैं। यह हमारी विधायिका की ही शक्ति है जो पक्ष और विपक्ष को एक मंच पर लाकर संवाद के दरवाजे खोल देती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 26 जुलाई 2007 की वो बैठक है। जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच 8 घंटे 40 मिनट तक closed door meetting हुई। जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी ने मिलकर नक्सल जैसी गंभीर समस्या पर खुलकर अपनी बात रखी। संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखकर ऐसे अनेकों कीर्तिमान रचते हुए हमारी विधानसभा ने 24 वर्षों की यात्रा पूरी की है।

एक लंबी यात्रा के बाद आज जब हम छत्तीसगढ़ की छठवी विधानसभा को देखते हैंए तब यह विधानसभा अपने युवावस्था के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैए आज जब हमारी विधानसभा में एक नई ऊर्जा और नव जनप्रतिनिधियों की प्रबल आवाज हैए इस परिपक्व होती हमारी विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व की मामले में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कुल 90 सदस्यीय सदन में अब तक सर्वाधिक 19 महिलायें निर्वाचित हो कर आई है जो कुल सदस्यों की 20 प्रतिशत है। 50 नए विधायकों में एक नया जज़्बा है और लगभग 14% विधायक हमारे सदन में ऐसे हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम हैए यानी कुल 13 युवा विधायक हमारी विधानसभा के सदस्य हैं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रत्येक विधान सभा के प्रारम्भ में नव.निवार्चित सदस्यों को संसदीय कार्य.प्रणाली, प्रक्रिया एवं परम्पराओं से अवगत कराने की दृष्टि से प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमे प्रबोधन के लिए छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों के विधान सभा के अध्यक्षों, भूतपूर्व मंत्रियों तथा वरिष्ठ सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के छठवें विधानसभा में जनवरी 2024 में प्रबोधन के लिए विशेष रूप से लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी, भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह, तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री माननीय श्री मनसुख मंडाविया, श्री सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा को भी आमंत्रित किया गया।

हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा ऐसी अनेकों ऐतिहासिक अवसरों की साक्षी बनी है, जिसने प्रदेश का गौरव बढाया हैए द्वितीय विधान सभा की अवधि में 28 जनवरी, 2004 को भारत के राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया जो भारत वर्ष के किसी भी राज्य की विधान सभा में राष्ट्रपति के संबोधन का यह पहला कार्यक्रम था। इसके बाद राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने भी जून 2011 में विधानसभा को सम्बोधित किया।

आज जब हम अपनी विधानसभा के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब छत्तीसगढ़ के साथ-साथ हमारे विधानसभा की अपनी युवावस्था में पहुंच चुकी है। इस युवावस्था में जब एक नौजवान सशक्त और आत्मनिर्भर होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी विधानसभा भी आत्मनिर्भर होकर एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। राजधानी के नवा रायपुर के सेक्टर 19 में महानदी (मंत्रालय) और इन्द्रावती (विभागाध्यक्ष) भवन के पीछे मध्य में नया विधानसभा भवन को 2025 तक पूर्णरूप से तैयार करने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जहाँ हमारी विधानसभा भारत-सरकार के जल-ग्रहण मिशन संस्थान के लिए बने भवन में संचालित थी, वहीं इस नई विधानसभा में हम सशक्तिकरण की नई गाथा लिखने जा रहे हैं। इस विधानसभा भवन में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएँ, नई तकनीक और डिजीटलीकरण का विजन भी समाहित है। इसके सदन में 200 सदस्यों की बैठक क्षमता एवं नए विधानसभा भवन में विधानसभा सचिवालय, विधानसभा का सदन, सेंट्रल-हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहां 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। नवीन विधानसभा भवन प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील है, जिसमें सौर ऊर्जा से संचालन के साथ ही पूरे भवन परिसर में अधिकाधिक वृक्षारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व टेक्नोलॉजी का समावेश और समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए भवन विकसित किया जा रहा है। इस नए विजन के साथ जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब समस्त प्रदेशवासियों को विधानसभा के 24वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और मंगलकामनाएं। हम सभी मिलकर आने वाले समय में अपने छत्तीसगढ़ को संवैधानिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएंगे एवं लोकतंत्र को सशक्त करते हुए विधानसभा की गरिमा को आगे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे।

'हंगामा क्यों बरपा' भागवत के बयान पर

बलबीर पुंज

बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या (प्रजनन दर) 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज पृथ्वी से लुप्त हो जाता है... इस तरह अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या विज्ञान का कहना है कि हमें 2 या 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। समाज को जीवित रखने के लिए संख्या महत्वपूर्ण है। जैसे ही उनका विचार मीडिया की सुर्खियों में आया, वैसे ही स्वयं-भू सैकुलरवादी और वामपंथी तिलमिला उठे।

संघ प्रमुख ने जिस आशंका को प्रकट किया है, उससे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय जनप्रतिनिधियों का एक समूह परिचित तो है, लेकिन अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण उसे जनविमर्श का हिस्सा बनाने से न सिर्फ बचता है, बल्कि उसे नया रंग देने का प्रयास भी करता है। आरोप-प्रत्यारोपों को दर-किनार कर क्या हमें हकीकत को नहीं देखना चाहिए? क्या यह सच नहीं कि भारतीय उप-महाद्वीप (भारत सहित) में हिंदुओं की जनसंख्या, मुस्लिमों के अनुपात में लगातार घट रही है? क्या मजहब का भारत की एकता-अखंडता और इस राष्ट्र के शाश्वत मूल्यों बहुलतावाद, लोकतंत्र और सैकुलरवाद के साथ सीधा संबंध है या नहीं? देश में जहां-जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक है, उनमें से अधिकतर क्षेत्र क्या अलगाववाद से ग्रस्त नहीं? संघ प्रमुख के विचार पर त्वरित कोई राय बनाने से पहले क्या इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोजने चाहिएं। क्या यह सत्य नहीं कि ब्रिटिशकालीन भारत, जनसांख्यिकीय में आए परिवर्तन के कारण ही विभाजित हुआ था? इस त्रासदी में जिन 2 मुल्कों पाकिस्तान और बंगलादेश का जन्म हुआ, वह घोषित रूप से इस्लामी हैं।

अपने वैचारिक अधिष्ठान के अनुरूप इन दोनों ही देशों में हिंदू, बौद्ध और सिख आदि अल्पसंख्यकों के लिए न तो कोई स्थान है और न ही उनके मानबिंदू (मंदिर-गुरुद्वारा सहित) सुरक्षित। विडंबना है कि सिंधु नदी, जिसके तट पर

हजारों वर्ष पूर्व ऋषि परंपरा से वेदों की रचना हुई उस क्षेत्र में आज उनका नाम लेने का कोई नहीं बचा है। भारतीय उप-महाद्वीप में सर्वाधिक 'असुरक्षित' कौन है? विश्व के इस भूखंड में कुल मिलाकर 180 करोड़ लोग बसते हैं, जिसमें भारत 140 करोड़, पाकिस्तान 23 करोड़ और बंगलादेश की आबादी 17 करोड़ है। 180 करोड़ में 112 करोड़ हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम 62 करोड़ से अधिक मुस्लिम। विभाजन से पूर्व, इस भू-भाग की कुल आबादी में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन अनुयायियों का अनुपात 75 प्रतिशत, तो मुस्लिम अनुपात 24 प्रतिशत था। स्वाधीनता से लेकर आज तीनों देशों में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन घटकर 62 प्रतिशत रह गए हैं, जबकि मुस्लिम बढ़कर 34 प्रतिशत हो गए।

आज हिंदुओं-सिखों-बौद्ध-जैन की जो वास्तविक संख्या 135 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए थी, वह घटकर 112 करोड़ रह गई है। यक्ष प्रश्न है कि इस भूखंड से पिछले 7 दशकों में 23 करोड़ हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन कहां गायब हो गए? बात यदि खंडित भारत की करें, तो अरुणाचल प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 5.56 प्रतिशत तक घट गई है। वर्ष 1971 में इस प्रदेश की कुल जनसंख्या में ईसाई एक प्रतिशत भी नहीं थे, लेकिन वर्ष 2011 में वे 30 प्रतिशत हो गए। इस दौरान बौद्ध अनुयायियों की संख्या भी घट गई है। असम में 2001 की जनगणनीय तुलना में हिंदू आबादी 2011 में लगभग 3 प्रतिशत घटी है। इस दौरान असम में हिंदू वृद्धि दर लगभग 11 प्रतिशत, तो मुस्लिम आबादी 29 प्रतिशत रही। प.बंगाल में भी हिंदुओं की वृद्धि दर तेजी से घट रही है। केरल में हिंदू जनसंख्या गत 100 वर्षों में 14 प्रतिशत घट चुकी है।

स्वतंत्रता से पहले नागालैंड और मिजोरम दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र थे। दिलचस्प तथ्य है कि वर्ष 1941 में नागालैंड की कुल आबादी में जहां ईसाई लगभग शून्य थे, तो मिजोरम में ईसाई आबादी आधा प्रतिशत भी नहीं थी। परंतु वह एकाएक 1951 में बढ़कर क्रमश- 46 और 90 प्रतिशत हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार, दोनों राज्यों की कुल जनसंख्या में ईसाई क्रमश- 88 और 87 प्रतिशत है। मेघालय की भी यही स्थिति है। इसी जनसांख्यिकीय स्थिति के कारण इन राज्यों में चर्च का अत्यधिक प्रभाव है। इसी वर्ष अगस्त-सिंतबर में मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अमरीका में भाषण देते हुए 3 देशों के ईसाई-बहुल क्षेत्रों को शामिल करते हुए 'ईसाई राज्य' के दृष्टिकोण को सांझा किया था। यहां अनुमान लगाना आसान है कि लालदुहोमा भारत, बंगलादेश और म्यांमार की बात कर रहे थे। इस षड्यंत्र का संकेत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दे चुकी थीं। यदि हिंदू बहुल भारत का एक तिहाई हिस्सा अगस्त 1947 में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन गया, तो 21वीं सदी से पहले ईसाई बहुल सर्बिया का हिस्सा रहे मुस्लिम बहुल कोसोवो ने 2008 में स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया।

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 104 देशों ने कोसोवो को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता भी दी है। इसी तरह मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया का अंग रहे ईस्ट तिमोर (तिमोर लेस्ते) ने मई 2002 में स्वयं को अपनी ईसाई बाहुल्यता के कारण आजाद मुल्क घोषित कर दिया। यही स्थिति ईसाई बाहुल्य दक्षिणी सूडान की भी है, जिसने इस्लामी राष्ट्र सूडान से कटकर स्वयं के स्वतंत्र होने का ऐलान कर दिया। यह उदाहरण है कि कैसे मजहबी-सांस्कृतिक भिन्नता, किसी देश का विखंडन कर सकती है। सच तो यह है कि देश के हिंदू चरित्र के कारण यहां पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और बहुलतावाद अब तक जीवित है। लेकिन यह भी उसी हद तक ही जिंदा रह सकती है, जब तक सनातन अनुयायियों की संख्या है। कोई भी विचार और संस्कृति केवल अपनी गुणवत्ता के बल पर ही सांस नहीं ले सकती, संख्याबल भी उतनी जरूरी है।

सीनियर और जूनियर पवार के बंगले भी आमने सामने

नीरज कुमार दुबे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने हालिया विधानसभा चुनावों में अपनी शक्ति और जनाधार का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए अपने आप को बड़ा मराठा नेता साबित करने में सफलता हासिल की। अजित पवार को खासतौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे अनुभवी नेता की भावुक अपीलों और उनकी चुनावी रणनीतियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा था। देखा जाये तो पिछले एक साल में अजित पवार को मुख्यमंत्री पद छोड़ कर वह सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर उनका अधिकार हो गया है और सर्वाधिक विधायक जिताने में भी वह सफल हुए। छठी बार उपमुख्यमंत्री बन कर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा नहीं पहुँचा पाये तो राज्यसभा सांसद बनवा दिया। अजित पवार ने जिस तरह अपने चाचा से राजनीतिक मुकाबला किया उसको देखकर भाजपा बेहद खुश है क्योंकि वह पवार के क्षेत्र में उन्हें घेरने में अब तक नाकामयाब रही थी लेकिन उनके भतीजे को साथ लेकर उसने सीनियर पवार की शक्ति कम करने में सफलता हासिल कर ली है। इसके अलावा जिस तरह अजित पवार भाजपा का साथ दे रहे हैं उससे भी पार्टी नेतृत्व बहुत खुश है। हाल ही में जब प्रश्न आया था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो अजित पवार ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया था। इसके बाद एक खबर आई कि आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके परिवार से 2021 में जब्त की गई 1,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को छोड़ दिया है क्योंकि बेनामी संपत्ति लेनदेन निवारण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अजित पवार पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया गया है। हम आपको याद दिला दें कि आरोप लगाया गया था कि अजित पवार और उनका परिवार बेनामी संपत्तियों का मालिक था। अब भाजपा नेतृत्व ने शरद पवार के मुकाबले अजित पवार को फिर से आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को एक बड़ा सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है। खास बात यह है कि यह सरकारी बंगला शरद पवार के घर के ठीक सामने है। हम आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार को सरकारी आवास की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी, टाइप- VII बंगला, 11 जनपथ पर आवंटित किया गया है, जो शरद पवार के आधिकारिक आवास के एकदम सामने है। सीनियर पवार 6 जनपथ पर टाइप-VII बंगले में रहते हैं और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो चार बार से लोकसभा सांसद हैं, वह उनके साथ रहती हैं। सुनेत्रा पवार को लुटियंस दिल्ली में टाइप-VII बंगले का आवंटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहली बार सांसद बनी हैं और नियमों के अनुसार वह दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी के आवास की हकदार नहीं हैं। इसलिए इस आवास के आवंटन को राजनीतिक हलकों में हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बड़े मराठा नेता के रूप में उनके पति अजित के उदय और सीनियर पवार पर उनकी बढ़त को मान्यता देने के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि अजित की राकांपा, जो भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में सहयोगी दल के रूप में लड़ी थी, उसने 49 सीटें हासिल कीं और मराठवाड़ा क्षेत्र और उनके गृह क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हम आपको याद दिला दें कि सुनेत्रा को 18 जून को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। सुनेत्रा बारामती लोकसभा सीट पर अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थीं। बाद में अजित ने कहा था कि सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारना उनकी गलती थी। बहरहाल, राजनीतिक मुकाबले के बावजूद पवार परिवार बड़े मौकों पर एकजुटता दिखाने का प्रयास भी करता है। गुरुवार को शरद पवार के जन्मदिन पर उनके दिल्ली स्थित आवास पर उन्हें बधाई देने खुद अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार और सहयोगियों प्रफुल्ल पटेल तथा छगन भुजबल के साथ पहुँचे।

'पड़ोसी पहले' वाली नीति लागू करे भारत

विपिन पब्बी

जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की सफलताएं विदेशों में स्पष्ट हैं, भारत के तत्काल पड़ोस में समस्याएं बनी हुई हैं, जहां लगभग सभी पड़ोसी देशों को भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के बावजूद भारत से समस्याएं हैं। 2014 में मोदी सरकार के आगमन के बाद, भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार हुआ था और नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बैठकों के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल स्पष्ट था। हालांकि 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अक्साई चिन पर टिप्पणी और 2020 में गलवान घाटी में झड़पों के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके कारण पिछले कई दशकों में भारत-चीन संबंधों में सबसे खराब स्थिति रही। दोनों देशों के 50,000 से अधिक सैनिक 3 साल से अधिक समय तक लद्दाख क्षेत्र में आमने-सामने रहे। हाल ही में मोदी और शी के बीच बैठक के बाद तनाव कम करने की दिशा में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों को पूर्ण विश्वास बहाली से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है।

चीन की तरह ही पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और यहां तक कि पड़ोसी देश का अनिर्धारित दौरा भी किया था। पुलवामा हमले और पाकिस्तान के अंदर बालाकोट हमलों के बाद संबंधों में गिरावट आई। तब से यह रिश्ता ठंडे बस्ते में है। दोनों देशों के नागरिकों के लाभ के लिए अपार संभावनाएं होने के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य अब ठप्प है। लेकिन सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव सहित अन्य पड़ोसी देशों से संबंधित है। जबकि भारत बंगलादेश में अब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन कर रहा था, जाहिर है कि उसने उस देश में उनके शासन के खिलाफ व्याप्त गहरी नाराजगी को भुनाने में सफलता नहीं पाई।

यह तथ्य कि वह अपने खिलाफ जन-विद्रोह के बाद भारत भाग गई हैं और यहां शरण लिए हुए हैं। यह भी

कुछ ऐसा है जो न तो अंतरिम सरकार और न ही बंगलादेश के नागरिकों को पसंद आ रहा है। उस देश में मंदिरों और हिंदुओं पर हिंसक हमले बंगलादेश के गठन के बाद से सबसे खराब हैं, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोदी सरकार को यह समझने की जरूरत है कि देश में हिंदू-मुस्लिम की कहानी पड़ोसी देशों में भी अपना असर दिखा रही है। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) के संभावित कार्यान्वयन ने इस धारणा को और बढ़ा दिया है कि कई अवैध प्रवासी बंगलादेश से भारत में घुस आए हैं।

नेपाल के साथ भी हमारे संबंध इस समय बहुत खराब चल रहे हैं। पिछले एक दशक में नेपाल को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने के बावजूद, नेपाल के चीन की ओर झुकाव को रोकने के भारत के प्रयास विफल हो गए हैं। पहली बार नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना है, जबकि परंपरा यह है कि नए प्रधानमंत्री अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत आते हैं। नए प्रधानमंत्री के.पी. ओली का भारत को लुभाने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। नेपाल के नागरिकों में यह धारणा बनी हुई है कि भारत ने 2015 में आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन किया था। हालांकि सरकार इस आरोप से इन्कार करती रही है।

नेपाल सरकार ने हाल ही में नेपाल के नए नक्शे के साथ करंसी नोट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के साथ विवादित कुछ क्षेत्रों को नेपाल की सीमा में दिखाया गया है। यहां तक कि भूटान भी चीन का इस्तेमाल कर अपनी ताकत दिखा रहा है। श्रीलंका में हाल ही में नैशनल पीपुल्स पावर (एन.पी.पी.) का उदय हुआ है, जो एक केंद्र-वामपंथी संगठन है जो 2019 में ही अस्तित्व में आया है। हालांकि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत आने वाले हैं, लेकिन उनकी पार्टी का मार्क्सवादी झुकाव चीन के प्रति श्रीलंका की विदेश नीति को एक झुकाव प्रदान कर सकता है।

इसी तरह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी मालदीव के साथ हमारे संबंध भी खराब हैं। इसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू एक जाने-माने भारत विरोधी हैं और उनकी पार्टी ने 'इंडिया आऊट' अभियान के दम पर चुनाव जीता था। उन्होंने निर्वाचित होने के तुरंत बाद मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए दबाव डाला और चीन द्वारा समर्थित नई परियोजनाओं का वायदा किया था। उन्होंने भारत की अनदेखी करके चीन की अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा की, हालांकि बाद में वे भारत आए।

नुकसान भी पहुंचा सकता है
हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध पीकर ज्यादातर लोग अपनी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए हल्दी वाला दूध नुकसानदायक साबित हो सकता है। लोग दादी-नानी के जमाने से हल्दी वाले दूध को सेहत के लिए वरदान मानते हैं। हालांकि, ज्यादा हल्दी वाला दूध पीने से आपकी सेहत पर पॉजिटिव असर की जगह नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को हल्दी वाला दूध पीने से बचना चाहिए।

गट हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

जिन लोगों को गैस या फिर ब्लोटिंग जैसी पेट से जुड़ी समस्या रहती है, उन्हें हल्दी वाले दूध को अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। हल्दी वाले दूध में पाए जाने वाले तत्व आपकी इस समस्या को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज जैसी साइलेंट किलर बीमारी के मरीजों को भी डॉक्टर की सलाह लिए बिना हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए।

ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स

अगर आपको अक्सर लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपके लिए हल्दी वाला दूध काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। हल्दी वाला दूध ब्लड प्रेशर को और ज्यादा लो कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको दूध से एलर्जी है, तो भी आपको हल्दी वाले दूध को अपने डाइट प्लान में शामिल करने से बचना चाहिए वरना आपकी सेहत को लेने के देने भी पड़ सकते हैं।

गौर करने वाली बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरसाती मौसम में भी हल्दी वाला दूध पीने से बचना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक हल्दी वाला दूध आपके लिए तभी फायदेमंद साबित हो सकता है, जब आप इसका सेवन लिमिट में रहकर करें। दरअसल, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से आपकी सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है।

काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है
विटामिन डी की कमी

शरीर में पोषक तत्वों की कमी सेहत को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन डी का नाम भी पोषक तत्वों की इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पैदा हो जाए, तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी को अंदर से खोखला कर सकती है। हालांकि, आप हेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान को फॉलो कर इस विटामिन की कमी को पैदा होने से रोक सकते हैं।

अगर आप अपने शरीर में इस विटामिन की कमी को पैदा होने से रोकना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट प्लान में खाने की कुछ चीजों को जरूर शामिल कर लेना चाहिए। फिश, अंडा और मशरूम खाने से आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी के पैदा होने के खतरे को कम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोया में भी विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है इसलिए इसे भी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

स्वाद में कड़वा जहर जैसा लगने वाला करेला सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है। कुछ लोगों को करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। आपको बता दें जितना कड़वा करेला स्वाद में होता है शरीर के लिए उतना ही ज्यादेमंद है। दरअसल करेला में ऐसे पोषक तत्त्व पाए जाते हैं जो डायबिटीज और कई दूसरी बीमारियों में असरदार काम करते हैं। भले ही सब्जी के रूप में करेला आपको पसंद न हो लेकिन इसे दवा समझकर ही अपनी डाइट में शामिल कर लें। आचार्य बालकृष्ण की मानें तो करेले का उपयोग सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि लगाने में भी किया जाता है। आइये जानते हैं करेला कौन सी बीमारियों में फायदा करता है और इसका सेवन कैसे करें?

स्वाद में कड़वा लेकिन
गुणों की खान है करेला

डैंड्रफ दूर

झकुछ लोगों को डैंड्रफ यानि रूसी की समस्या रहती है। उनके लिए करेला का रस फायदेमंद हो सकता है। डैंड्रफ हटाने के लिए आप करेले के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करेले के पत्तों का रस निकालकर बालों पर लगा लें। आप इस जूस में थोड़ी हल्की मिलाकर उपयोग करें डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा।

सिरदर्द में आराम

झअगर आपको हमेशा सिरदर्द की परेशानी होती है तो आप करेले की पत्तियों को पीस कर इसका रल सिर में लगाएं। इस रस को अपने माथे पर लगा लें और सिर पर मालिश जैसी कर लें। काफी राहत मिलेगी।

मुंह के छाले दूर करे

अक्सर गर्मियों में मुंह में छाले हो जाते हैं। जिससे खाने पीने में परेशानी होती है। ऐसे में आप कई तरह के नुस्खों का उपयोग करते है, लेकिन उनका कोई खास आराम नहीं मिलता है। आप एक बार करेले का रस छालों पर लगा लें। इससे काफी फायदा मिलेगा। रस लगाने के बाद लार को बाहर निकलने दें और कुछ देर मुंह खोलकर लटकाए रखें। छाले 1 दिन में ही ठीक हो जाएंगे।

पथरी दूर करे

झ करेले का जूस पीने से पथरी के मरीज को आराम मिलता है। जिन लोगों को पथरी की परेशानी है, उन्हें करेले का रस जरूर पीना चाहिए। इससे पथरी को नेचुरली निकालने में मदद मिलती है।

घुटनों के दर्द में फायदेमंद

जिन लोगों को अक्सर घुटनों में दर्द होता रहता है। ऐसे लोग भी करेला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कच्चे करेले को आग में भून लें। अब करेला को मसल लें और रुई में लपेट कर घुटने में बांध लें। इससे जोड़ों और घुटने के दर्द में काफी आराम मिलेगा।

लटकती तोंद
हो जाएगी अंदर, बस रात को पिएं ये 5 ड्रिंक्स

हमारी लाइफस्टाइल के कारण बेली फैट बढ़ना एक आम समस्या बन चुकी है। कई लोग पेट की चर्बी बढ़ने की समस्या से परेशान रहते हैं। इसके लिए वे कई तरह की डाइट भी ट्राई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछऐसी ड्रिंक्स हैं, जिन्हें रात के समय पीने से बेली फैट कम करने में काफी मदद मिल सकती है। यहां हम उन्हीं ड्रिंक्स के बारे में जानेंगे, जो आपके पेट पर जमा जिद्दी चर्बी को पिघलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानें क्या हैं वे ड्रिंक्स।

ये ड्रिंक्स नेचुरल चीजों से बनती हैं, जो मेटाबॉलिज्म को तेज बनाने में मदद करते हैं। इसलिए इन्हें पीने से फैट बर्न करने में सहायता मिलती है और पाचन भी दुरुस्त रहता है। इन कारणों से ये ड्रिंक्स बेली फैट घटाने में काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

सोने से पहले कौन-से ड्रिंक्स पेट कम करने में मदद कर सकते हैं?

ग्रीन टी- ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैटेचिन होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और फैट बर्निंग को बढ़ावा देते हैं। सोने से पहले एक कप ग्रीन टी पीने से आपको रात भर कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है।

अदरक की चाय- अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है और पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। सोने से पहले एक कप अदरक की चाय पीने से आपको रात भर आरामदायक नींद आएगी।

दालचीनी पानी- दालचीनी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी में थोड़ी-सी दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है।

नींबू पानी- नींबू में विटामिन-सी होता है, जो इम्युनिटी को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से आपको डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिल सकती है।

पुदीने की चाय- पुदीना पाचन को बेहतर बनाता है और पेट की गैस को कम करता है। सोने से पहले एक कप पुदीने की चाय पीने से आपको आरामदायक नींद आएगी।

बेली फैट कम करने के लिए कौन-सी ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए?

शराब- शराब पीने से कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।

कॉफी और चाय- कॉफी और चाय में कैफीन होता है, जो नींद आने में बाधा बन सकती हैं, जिस वजह से वजन बढ़ सकता है।

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में शुगर और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है।

पैकेट वाले जूस- जूस में फ्रक्टोज होता है, जो वजन बढ़ने का कारण बन सकता है।

सर्दी में नुकसानदायक साबित हो सकती हैं खाने की ये चीजें

सर्दियों में लोगों को अक्सर सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। खांसी के साथ-साथ कफ और बलगम भी लोगों की उलझन का कारण बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि खाने की कुछ चीजों का सेवन करने की वजह से बलगम की समस्या बढ़ सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिस्टामाइन से भरपूर फूड आइटम्स बलगम के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि बलगम की समस्या से जूझ रहे लोगों को इन चीजों को खाने से बचना चाहिए।

मेयोनीज- अगर आप बलगम की समस्या को बढ़ने नहीं देना चाहते, तो आपको मेयोनीज का सेवन नहीं करना चाहिए। मेयोनीज आपकी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज करने का कारण बन सकती है जिसकी वजह से बलगम की समस्या बढ़ सकती है।

खट्टे फल- हेल्थ एक्सपर्ट्स सर्दी, खांसी और जुकाम से जूझ रहे मरीजों को खट्टे फल न खाने की सलाह देते हैं। खट्टे फलों को खाकर गले से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक बढ़ सकती हैं।

चॉकलेट/कॉफी- क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट या फिर कॉफी जैसी चीजें बलगम के प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर सकती हैं। इसके अलावा आपको प्रोसेस्ड मीट्स का सेवन करने से भी बचना चाहिए वरना आपकी बलगम की समस्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है।

तला हुआ खाना- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तला हुआ खाना भी बलगम की समस्या को बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए सर्दी, खांसी या फिर जुकाम जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए तला हुआ खाना न खाएं।

दही- अगर आप बलगम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको दही को अपनी डेली डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए। दही बलगम के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है जिसकी वजह से आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं।

यूरिक एसिड कंट्रोल करने में ये जड़ी-बूटी है फायदेमंद

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हल्के-फुल्के दर्द को गंभीरता से न लेते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही एक दर्द है, पैरों की एड़ी में अचानक शुरू हुआ दर्द और उससे जुड़ी हुई सूजन, जिसकी मुख्य वजह है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। अगर समय रहते इसे कंट्रोल न किया जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, जैसे, गठिया, शुगर, जोड़ों से दर्द, सूजन आदि शामिल हैं। यहां तक की किडनी में स्टोन और किडनी के फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में दवाइयों के अलावा कुछ आयुर्वेद अपनाने के साथ ही खान-पान में थोड़े बदलाव कर आप यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। इसी आयुर्वेद में से एक गिलोय है। आइए जानते हैं गिलोय किस तरह से यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में असरदार है।

यूरिक एसिड कंट्रोल करेगा गिलोय-

गिलोय एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। ये कई बीमारियों में असरदार है। अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं तो गिलोय इस समस्या को भी कंट्रोल करने में कारगर है। इसमें गिलोय में अधिक मात्रा में एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व पाएं जाते हैं जो यूरिक एसिड के लक्षणों को कम करता है। इसके लिए बस आपको इसके इस्तेमाल के सही तरीके की जानकारी होनी चाहिए।

यूरिक एसिड से पीड़ित मरीज इस तरह करें गिलोय का इस्तेमाल

रोजाना गिलोय का इस्तेमाल करना लाभकारी होगा। इसके लिए सबसे पहले गिलोय की ताजी पत्तियों और तने को तोड़ लें। उसके बाद इसे रात भर भिगोकर रख दें। अगले सुबह इसे पीस लें। उसके बाद 1 गिलास पानी और इस पाउडर को पैन में डालें और गैस पर चढ़ा दें। अब इसे आधा होने तक उबालें। उसके बाद इसे छानकर पी लें।

सर्दी में रोज दूध के साथ खाएं एक गोंद का लड्डू

सर्दियों का मौसम आ चुका है। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और तंदुरुस्त रखना जरूरी होता है, ताकि सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसलिए इस मौसम में गोंद के लड्डू खाना काफी फायदेमंद होता है।

गोंद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं।

साथ ही, इससे बने लड्डुओं में घी और सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, जो शरीर को गर्म रखते हैं और पोषण देते हैं। इसलिए सर्दी के मौसम में रोज एक गोंद के लड्डू खाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां हम गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप आसानी से घर पर इन्हें बना सकते हैं।

गोंद के लड्डू बनाने की विधि

सामग्री - गोंद - 100 ग्राम
सूखा मेवा (बादाम, काजू, किशमिश) - 100 ग्राम
घी - 100 ग्राम, गेहूंका आटा - 250 ग्राम
चीनी - 200 ग्राम, इलायची पाउडर - 1/2 चम्मच
सूखी अदरक पाउडर - 1/4 चम्मच
एक पैन में घी गर्म करें और उसमें गोंद डालकर सुनहरा होने तक भून लें।
एक अलग पैन में सूखे मेवे को हल्का-सा भून लें।
एक कड़ाही में गेहूं का आटा हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
भूने हुए गोंद, सूखे मेवे, आटा, चीनी, इलायची पाउडर और सूखी अदरक पाउडर को एक बर्तन में मिला लें।
इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर छोटे-छोटे लड्डू बना लें।
लड्डू को ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।

गोंद के लड्डू खाने के फायदे

हड्डियों को मजबूत बनाते हैं- गोंद में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

जोड़ों के दर्द में आराम- गोंद में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं- गोंद पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है।

इम्युनिटी बढ़ाते हैं- गोंद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

सर्दी-खांसी में लाभकारी- गोंद गले की खराश और खांसी में आराम दिलाता है।

एनर्जी देते हैं- गोंद में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं।

किन लोगों को गोंद के लड्डू नहीं खाने चाहिए?

डायबिटीज के मरीज- चीनी की मात्रा ज्यादा होने के कारण डायबिटीज के मरीजों को गोंद के लड्डू सीमित मात्रा में या नहीं ही खाने चाहिए।

मोटापे से पीड़ित लोग- कैलोरी की मात्रा ज्यादा होने के कारण मोटापे से पीड़ित लोगों को गोंद के लड्डू कम मात्रा में ही खाने चाहिए।

लो इम्यूनिटी को तेजी से बूस्ट करता है गुड़

खांसी जुकाम में गुड़ खाने के फायदे- मौसमी इंफेक्शन और खांसी जुकाम में अक्सर कहा जाता है गुड़ खा लो। आज से नहीं दादी-नानी के जमाने से गुड़को इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के रूप में देखा जाता है। लोग इसे अजवाइन के साथ लेते हैं। गुड़ का शरबत पीते हैं, गुड़ की चाय लेते हैं और फिर आप गुड़ को गर्म पानी के साथ कई प्रकार से ले सकते हैं। पर समझने वाली बात ये है कि गुड़ इम्यूनिटी बूस्ट क्यों और कैसे, जानते हैं इसके तमाम उन खास गुणों के बारे में जो हमें बीमारियों से बचा सकते हैं। गर्मी पैदा करता है गुड़- गुड़ की खास बात ये है कि इसे खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। ये आपके शरीर के तमाम अंगों को एनर्जी देता है और मौसमी बदलाव के साथ शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये शरीर के बाहरी और अंदरूनी तापमान के बीच एक संतुलन बनाने में मदद करता है जिससे आप अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण बीमार नहीं पड़ते। गुड़ है एंटी इंफ्लेमेटरी है- गुड़ एंटी बैतक्टीरियल गुणों से भरपूर है और शरीर में सूजन को रोकने मे मदद करता है। इस वजह से सर्दी-जुकाम में इसे खाना फायदेमंद हो जाता है। इससे गले की खराश समेत कई समस्याओं में कमी आती है। इसके अलावा सिर दर्द और कमजोरी में भी ये मददगार है क्योंकि गुड़ में आयरन है और ये आयरन रेड ब्लड सेल्स को बढ़ावा देता है।

गुड़ इम्यूनिटी बूस्टर है- गुड़ एंटीबैक्टीरियल है। ये टी सेल्स को बढ़ावा देता है और शरीर को मौसमी इंफेक्शन से बचाता है। इससे होता ये है कि आप कई मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं। जैसे अचानक से फ्लू होना। सूखी खांसी और कफ की समस्या में भी गुड़ का सेवन करना कई प्रकार से फायदेमंद है। तो, सर्दियां आ रही हैं तो अपनी डाइट में गुड़को शामिल कर लें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं : जगदीप धनखड़

नईदिल्ली। अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जारी विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच शुक्रवार को राज्यसभा में एक बार फिर नोकझोंक हुई, जिससे संसद के ऊपरी सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों के साथ बहस करते हुए धनखड़ ने एक बार कहा कि वह देश के लिए मरेंगे। धनखड़ ने खड़गे और अन्य कांग्रेस सांसदों से हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं देश के लिए मर जाऊंगा। संसद में 24 घंटे आपका यही एकमात्र मुद्दा है- एक किसान का बेटा यहां उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर क्यों बैठा है। बोलने से पहले सोचें। मैंने काफी सहन किया है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा। राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। मैंने आपसे अधिक चुनौतियों का सामना किया है। आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं।

कांग्रेस ने केजरीवाल की सीट से संदीप दीक्षित को उतारा

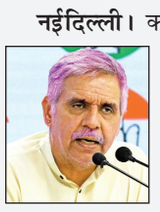

नईदिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की, जिसमें पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल करते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि केजरीवाल ने 2013 में नई दिल्ली से संदीप की मां शीला दीक्षित को हराया था और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस ने बादली से दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव, बल्लीमारान से हारून यूसुफ, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, द्वारका से आदर्श शास्त्री और चांदनी चौक से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले होने वाले हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लोकतंत्र को नष्ट करने भाजपा की चाल

मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' लोकतंत्र को नष्ट करने की भाजपा की चाल है और पार्टी अपने ''स्वार्थी'' उद्देश्य के लिए इस विधेयक पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा अपने स्वार्थी उद्देश्य के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र, एक चुनाव लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करने की चाल है। उन्होंने कहा कि राज्य और राष्ट्र से संबंधित मुद्दे अलग-अलग होते हैं और लोगों को उसी के अनुसार मतदान करना होता है। राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, आपने अभी तक बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) के चुनाव नहीं कराए हैं। हार के डर से आपने नगर निकाय चुनाव नहीं कराए।

आप के आरोपों को गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने किया खारिज

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के संबंध में अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और आम आदमी पार्टी (आप) को चेतावनी देते हुए मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी। आप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मुझ पर और मेरी पत्नी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने अपने 25 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ऐसे आरोपों का सामना नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम सावंत ने कहा कि आप नेताओं के पास उनकी सरकार के खिलाफ उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और यही मुख्य कारण है कि उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। सावंत ने आप नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इसलिए जो लोग उत्पाद घोटाले में जेल गए, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं, लेकिन लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट से पार्थ चटर्जी को मिली जमानत

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को राज्य में कैश-फॉर-स्कूल जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत को 31 दिसंबर को पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला करना चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि पूर्व मंत्री पिछले दो साल और दो महीने से जेल में हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस साल अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को रिहा किया जाएगा। अगर आरोप तय करने और गवाहों की जांच पहले हो जाती है, तो उन्हें इसके तुरंत बाद भी रिहा किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें विधानसभा का सदस्य होने के अलावा किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

एक नेता संविधान की प्रति जेब में रखते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा: राजनाथ

■ **लोकसभा में संविधान पर दो दिवसीय बहस शुरू, रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज**

नई दिल्ली। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम पूरा किया था। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था, वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था बल्कि वह जनआकांक्षाओं का प्रतिबिंब था।

राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान से देश में सही मायने में लोकतंत्र लागू हुआ। हमारा संविधान सार्वभौम है, जहां यह राज्य की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है तो वहीं नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लेख करता है। हमारा संविधान सहकारी सघंवाद को सुनिश्चित करता है तो राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान देश के गौरव को स्थापित करने का रोडमैप भी है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को उपनिवेशवाद का उपहार या अच्छी बातों का संकलन मात्र मान लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को नकार दिया गया।

अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्टी विशेष के नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर चलते हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है। राजनाथ सिंह का यह तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर माना जा रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, लेकिन इसके निर्माण के कार्य को एक पार्टी विशेष द्वारा 'हाईजैक' करने की कोशिश हमेशा की गई है। उन्होंने लोकसभा में 'भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को 'हाईजैक' करने की कोशिश हमेशा से की गई है। भारत में संविधान निर्माण के इतिहास से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, %आज विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा है, लेकिन भाजपा संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति पूरी तरह साफ है।

राजनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को जब भी सत्ता और संविधान में से किसी एक को चुनना था तो उन्होंने हमेशा सत्ता को चुना। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी संस्था की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं हैं। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत, हमारे मन में, वचन में, कर्म में, हर जगह दिखाई पड़ेंगे।

उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए, उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था, सामाजिक कल्याण था और लोगों का सशक्तीकरण था।

राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया। हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया है। और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा कष्ट भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, ताकि भारत की अखंडता सुनिश्चित हो। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी सामाजिक न्याय की भावना से ही प्रेरित था। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अतीत में सिर्फ संविधान संशोधन नहीं किया, बल्कि दुर्भावना के साथ धीरे-धीरे संविधान बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पंडित जवारलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया।

संविधान सुरक्षा कवच है, भाजपा ने इसे तोड़ने का काम किया : प्रियंका गांधी

लोकसभा में अपने पहले भाषण में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने मौजूदा सरकार पर भारत के संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, प्रियंका ने जोर देकर कहा कि सरकार के कार्य संविधान में निहित मूल मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान राष्ट्र की आवाज़ के रूप में कार्य करता है, इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इन्हें (भाजपा) हारते-हारते जीतने से एहसास हुआ कि इस देश में संविधान बदलने की बात नहीं चलेगी।

प्रियंका गांधी ने कहा कि संभल के शोक संतप्त परिवारों के कुछ लोग हमसे मिलने आये थे। इनमें दो बच्चे भी थे- अदनान और उज़ैर। उनमें से एक मेरे बेटे की उम्र का था और दूसरा उससे छोटा, 17 साल का था। उनके पिता एक दर्जी थे। दर्जी का एक ही सपना था - वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा और दूसरा भी सफल होगा। पुलिस ने उनके पिता को गोली मार दी। 17 वर्षीय अदनान ने मुझसे कहा कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपने पिता के सपने को साकार करेगा। यह सपना और आशा उनके दिल में भारत के संविधान ने पैदा की थी

कांग्रेस नेत्री ने कहा कि हमारा संविधान सुरक्षा कवच है। ऐसा सुरक्षा कवच जो नागरिकों को सुरक्षित रखता है- ये न्याय का, एकता का, अभिव्यक्ति के अधिकार का कवच है। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि 10 साल में बड़े-बड़े दावे करने वाले सत्ता पक्ष के साथियों ने इस कवच को तोड़ने की तमाम कोशिशें कीं। संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा करता है। ये वादे एक सुरक्षा कवच हैं और इसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए यह सरकार आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में जाति जनगणना से भागने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जाति जनगणना समय की मांग है और इससे हमें नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, यह सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि मेरे विपक्ष ने उस संविधान को तोड़ने की पूरी कोशिश की है जो हमारी रक्षा करता है। उन्होंने एकता को तोड़ना शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान जब विपक्ष ने जाति जनगणना कराने के लिए आवाज़ उठाई, तो वे मुद्दे से भटक गए। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने महिलाओं को शक्ति दी। नारी शक्ति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, क्या उन्हें 10 साल तक इंतजार करना होगा। गांधी ने कहा कि सत्ताधारी दल सिर्फ अतीत की घटनाओं की बात करता है, भविष्य के लिए काम नहीं कर रहा है। सरकार किसानों को सुरक्षा देने और बेरोजगारी व महंगाई का समाधान देने में असमर्थ है। देश की जनता को भरोसा था कि संविधान हमारी रक्षा के लिए है लेकिन अडानी मुद्दे ने उसे खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले (कांग्रेस सरकार के शासनकाल) संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर बात करेगी।

सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए देश की एकता को भी ताक पर रखा जा रहा। इनका कहना है कि देश के अलग-अलग हिस्से हैं, लेकिन संविधान कहता है कि देश एक है और एक ही रहेगा। जहां खुला संवाद और अभिव्यक्ति का कवच होता था, वहां इन्होंने भय का माहौल पैदा किया। इस देश की जनता ने निडर होकर देश की सत्ता को ललकारा, उन्हें चेतावनी दी, उनसे जवाब मांगा। इस देश के घर-घर, गली-मोहल्ले और न्यायपालिका में चर्चाएं कभी बंद नहीं हुईं, लेकिन आज जनता को सच बोलने से डराया-धमकाया जाता है। सभी का मुंह बंद कराया जाता है, किसी पर ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा।

प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था, जब इस तरफ बैठे हुए गांधी विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं उस तरफ के लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे। भय फैलाने वाले खुद भय का शिकार हो जाते हैं। आज इनकी भी यही स्थिति हो गई है। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। इनमें चर्चा की हिम्मत नहीं है। आज के राजा में न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। यह देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसे बनाने वाले किसान, मजदूर और करोड़ों जनता है। ये देश भय से नहीं चल सकता। भय की भी एक सीमा है, जब उसे इतना दबाया जाता है और उसके पास उठ खड़े होने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से

ब्रिस्बेन। भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में अभी तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। वहीं तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर शनिवार से ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। जो कि भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे से खेला जाएगा।

वहीं गाबा की पिच को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो सकती है, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है। पिच से तेज गेंदबाजों को पेस और बाउंस मिलेगा, यानी बल्लेबाजों की शामत आनी तय है। शुरुआती दिन तो यहां पर गेंदबाजों का ही बोलबाला रहेगा। जो भी टीम यहां टॉस जीतेगी, शायद वो पहले गेंदबाजी करेगी। वैसे भी दोनों ही टीमों में धुरंधर तेज गेंदबाजों की कम नहीं है।

अब गाबा टेस्ट में जिस पिच पर भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है, उसकी तस्वीरें सामने आई है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि पिच तेज गेंदबाजों के ही मुफीद होगी। विकेट काफी हरा-भरा दिख रहा है और इस पर लगातार रोलिंग की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट पहले ही से ग्रीन टॉप पर विकेट बनवाने के मूड में था, ताकि सीरीज में बढ़त ली जा सके। हालांकि, ये फैसला बैकफायर भी कर सकता है क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजी यूनिट ऑस्ट्रेलिया से कमतर नहीं है।

2020-21 गाबा टेस्ट को कौन भूल सकता है। यही वो समय था जब भारत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया को इस मैदान पर भारत से हार के कारण बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवानी पड़ी थी। उस मैच से पहले मेजबान टीम 1988 से गाबा में अपराजित थी। पिछली गर्मियों में भी उसे इस मैदान पर वेस्टइंडीज के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स में 843 अंक की बढ़त निफ्टी 24,800 के करीब

नईदिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन पर शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती गिरावट से उबरकर 843.16 अंकों यानी 1.04त्न की बढ़त के साथ 82,133.12 पर बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स ने 82,192.61 के ऊपरी स्तर और 80,082.82 के निचले स्तर पर कारोबार किया। एनएसई निफ्टी50 भी 219.60 अंकों यानी 0.89त्न की बढ़त के साथ 24,768.30 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में निफ्टी ने 24,792.30 का ऊपरी स्तर और 24,180.80 का निचला स्तर छुआ। शुक्रवार का दिन बुल्स के पक्ष में रहा। निफ्टी के 50 में से 41 स्टॉक्स हरे निशान पर बंद हुए। इनमें भारती एयरटेल, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों में 4.44त्न तक की बढ़त देखी गई। वहीं, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे 9 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए।

पीएफ धारक नए साल से एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा

नईदिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों के लिए बड़ी सुविधा लाने की तैयारी में है। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कथित तौर पर एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि जल्द ही ईपीएफओ सदस्य एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। यह नई सुविधा मई-जून 2025 तक शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय भारतीय कार्यबल को बेहतर सेवाएं देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इससे पीएफ दावे दाखिल करने और उनका निपटारा करना पहले से आसान हो जाएगा। डावरा ने कहा कि जनवरी 2025 तक ईपीएफओ के सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

अशोक लेलैंड ने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ाए

नईदिल्ली। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। कंपनी ने सीवी की अपनी पूरी रेंज की कीमतें जनवरी 2025 से 3 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है। शुक्रवार को कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। इससे पहले, टाटा मोटर्स भी अपने सीवी की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। अशोक लेलैंड ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक, मॉडल और वेरिएंट के आधार पर यह बढ़ोतरी अलग-अलग होगी। कंपनी का कहना है कि महंगाई और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बाद दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। इससे कंपनी को इनपुट कॉस्ट की बढ़ती लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले, टाटा मोटर्स ट्रकों और बसों की कीमत 1 जनवरी, 2025 से 2 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है।

जियो के बाद एयरटेल का न्यू ईयर का धमाकेदार ऑफर

नईदिल्ली। रिलायंस जियो के न्यू ईयर वेलकम प्लान के बाद एयरटेल ने भी अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार प्रीपेड प्लान की पेशकश की है। इस प्लान को रिचार्ज करने पर ग्राहक 200 दिनों तक इस प्लान का लाभ उठा सकेंगे। एयरटेल के नए प्लान की कीमत 398 रुपये है। इस प्लान में यूजर्स को पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलेगा। साथ ही, अनलिमिटेड 5जी डेटा भी मिलेगा, जिसमें हर दिन पहले 2जीबी डेटा हाई-स्पीड पर मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ 5जी स्मार्टफोन वाले यूजर्स के लिए है। इसके अलावा, ग्राहकों को रोजाना 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। यह प्लान 28 दिनों तक वैध है और इसमें Disney+ Hotstar Mobile Edition का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। एयरटेल के अन्य प्लान भी मौजूद हैं।

बैंकिंग संशोधन बिल से रुकेगी धोखाधड़ी

सतीश सिंह

लोकसभा में विगत तीन दिसंबर को बैंकिंग संशोधन बिल, 2024 पारित किया गया। इसके तहत बैंकिंग क्षेत्र में कुल 19 बदलाव किये जायेंगे, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 आदि कानूनों में संशोधन करने के बाद संभव हो सकेगा। संशोधनों के पश्चात सात साल तक दावा न किये गये डिविडेंड, शेयर, ब्याज और परिपक्व बॉन्ड की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आइइपीएफ में अंतरित किये जा सकेंगे, जिससे धोखाधड़ी की वारदातों में कमी आयेगी और जमा राशि के वास्तविक दावेदार आइइपीएफ के जरिये निवेश की गयी राशि की निकासी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि वहां ऐसी फंसी राशि की निकासी की प्रक्रिया सरल एवं सहज होगी।

इन संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण बैंक खाते में एक की जगह चार नॉमिनी जोड़े जाने का प्रावधान है, क्योंकि मौजूदा समय में सिर्फ एक नॉमिनी नामांकित करने से धोखाधड़ी, साइबर अपराध, धनशोधन और आतंकवादी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज देश के बैंकों में लाखों ऐसे खाते हैं, जिनमें कोई नॉमिनी नहीं है। कई मामलों में नामांकित एक नॉमिनी की मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा जमा राशि का दावा न करने के कारण ऐसे खाते दो साल के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। मार्च, 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ की राशि का कोई दावेदार नहीं था। सरकार के अनुसार 2023 के अंत तक बैंक के निष्क्रिय खातों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा थी, जिनमें 42 हजार करोड़ रुपये राशि का कोई दावेदार नहीं था। फिलवक्त, दावा न की गयी

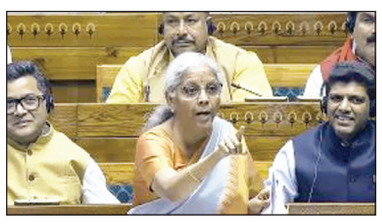

राशि में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार चाहती है कि निष्क्रिय खातों पर सतत निगरानी रखी जाये। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकों को निष्क्रिय खातों की रिपोर्ट तिमाही आधार पर जारी करने का निर्देश दिया है। आमतौर पर निष्क्रिय खातों में धोखाधड़ी की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे खातों का इस्तेमाल धनशोधन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। देश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने वित्तीय समावेशन और डिजिटाइजेशन की संकल्पना को मूर्त देने में बड़ी भूमिका निभायी है। विगत 13 नवंबर तक देश भर में खोले गये जन-धन खातों की संख्या करीब 53.99 करोड़ थी, जिनमें निष्क्रिय खातों की संख्या लगभग 11 करोड़ थी। जनधन खातों में करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये जमा थे। जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाता का होना और उनमें बड़ी राशि जमा होना आतंकी गतिविधियों, धोखाधड़ी और धनशोधन की आशंका को बढाता है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के पहले नौ महीनों में साइबर धोखाधड़ी के कारण खातेदारों को 11,333 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। बैंकों में बढ़ रहे निष्क्रिय खातों से रिजर्व बैंक बेहद चिंतित है। उसने बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसे खातों की केवाईसी के लिए वे मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, नॉन-होम शाखा, वीडियो केवाइसी आदि सरल प्रक्रिया अपनायें। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि ऐसे खातों में केंद्र या राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की जमा होने वाली राशि पर रोक नहीं लगानी चाहिए, ताकि जब लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य केवाइसी की प्रक्रिया पूरी पैसों की निकासी करें, तो उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। खातों के निष्क्रिय होने से खातेदारों को नुकसान होते हैं। बैंक ऐसे खातों में ब्याज की राशि जमा करना बंद कर देता है। बैंक में पैसा जमा न करने की वजह से उनका पैसा हमेशा जोखिम में रहता है अर्थात उसके चोरी होने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। वे ऑनलाइन लेन-देन का लाभ भी नहीं उठा पाते। निष्क्रिय खातों पर रख-रखाव या निष्क्रियता शुल्क लगाया जाता है। खाताधारक ऑनलाइन बैंकिंग या डेबिट व क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहन

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार देने पर उद्योगों को मिलेगा सब्सिडी

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साझा किए विचार

रायपुर। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रीयल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ऑनलाइन जुड़ कर यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पांच लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहित कई अन्य सहायता दी जा रही है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस नीति के तहत बस्तर में उद्योग लगाने पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के तहत उद्योगों को 45त्न तक की सहायता दी जाएगी। वहीं, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत अगले 10 सालों तक पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक एसजीएसटी वापस भी किया जाएगा। नई नीति के तहत उद्योगों को स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट, साथ ही 10 और तरह के निवेश प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट की सहायक इकाइयों के लिए 118 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री साय ने कहा नई उद्योग नीति में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 को शामिल किया गया है। इससे वे एक ही जगह पर कई विभागों का क्लीयरेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीति है। हम इस नीति में ग्रीन इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

नया रायपुर बनेगा आईटी और एजुकेशन हब- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नया रायपुर को आईटी हब, हेल्थ हब, एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईटी और संबंधित फर्मों को रियायती दरों पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहे हैं। आईटी सेक्टर में साढ़े तीन हजार से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए स्थान आबंटित किए गए हैं।

नया रायपुर अटल नगर की रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा हो गया है। उन्होंने बताया हम सीबीडी रेलवे स्टेशन के निर्माण, सड़कों और सार्वजनिक पार्किंग जैसी अधोसंरचनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तीन अन्य रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया इस साल के अंत तक नया रायपुर से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इनमें आईटी एवं संबंधित क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू उपकरण, रक्षा, फार्मास्युटिकल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य में अधोसंरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार से 31 हजार करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बस्तर और सरगुजा के अंदरुनी गांवों तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया रायपुर-विशाखापटनम इकॉनोमी कॉरिडोर, अनेक रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है। रायपुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं, नियद नेल्ला नार योजना के तहत बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है।

जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास पर जोर-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मिशन का 79त्न से अधिक काम पूरा हो चुका है और अब तक 40 लाख घरों में नल के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मल्टी-विलेज योजना के तहत उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जा रहा है, जहां भूजल की कमी है।

नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति

नक्सलवाद से निपटने में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस साल अनेक नक्सली मारे गए हैं और करीब 1500 ने आत्मसमर्पण किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अगले दो वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया है। बीते एक साल में बस्तर में 34 सुरक्षा कैम्प स्थापित करने के साथ-साथ नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से अंदरूनी गांवों तक अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है।

डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को लागू किया है। प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए आईटी उपकरणों में 266 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। अटल मॉनिटरिंग ऐप से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सकती है। स्वागत पोर्टल के माध्यम से पोर्टल में आवेदन देकर बिना इंतजार किए सुगमता से मंत्रालय में अधिकारियों से मिला जा सकता है। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासन-प्रशासन से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी त्वरित रूप से नागरिकों को मिल जाती है। वहीं, सुगम एप के माध्यम से अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य तैयार कर रहा है ईको-रेस्टोरेशन पॉलिसी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में ईको-रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। केरल के बाद, यह छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जो यह पॉलिसी तैयार कर रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

भारत की ग्लोबल रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, बॉन चैलेंज और संयुक्त राष्ट्र ईको-रेस्टोरेशन दशक में भागीदारी यह स्पष्ट करती है कि एक केंद्रित ईको-रेस्टोरेशन नीति अनिवार्य है। पारंपरिक वनीकरण, जो प्राय: अत्यधिक लागत वाला होता है और गैर-स्थानीय प्रजातियों पर आधारित होता है, सीमित पारिस्थितिक लाभ प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में अपने निर्देश के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने ईको-रेस्टोरेशन को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ईको-रेस्टोरेशन अत्यंत आवश्यक है। यह पहल एक अधिक समावेशी और सुदृढ़ पर्यावरणीय भविष्य सुनिश्चित

केरल के बाद देश का दूसरा राज्य होगा छत्तीसगढ़

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि ईको-रेस्टोरेशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के खोए हुए वन क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करना है। नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, हितधारकों एवं समाज के सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस पॉलिसी का अंतिम मसौदा जनवरी माह में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में दो राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। इन कार्यशालाओं में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के ईको-रिहैबिलिटेशन सेंटर के वैज्ञानिक, वानिकी विशेषज्ञ, भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के संकाय सदस्य और छात्र, कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, शोधकर्ता, शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोग, एनजीओ और समुदायों के प्रतिनिधि, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और अन्य विशेषज्ञों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इसके लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन, शहरी पारिस्थितिकी संरक्षण, और खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास जैसे विशिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त किए गए। कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के क्षेत्र में एक व्यापक और प्रभावशाली नीति बनाने में सक्षम बनाना है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी।

शीतकालीन सत्र: सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति

रायपुर। नवा रायपुर, अटल नगर स्थित नवीन मुख्यमंत्री निवास में आज भाजपा विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में आगामी सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का

प्रभावी ढंग से जवाब देने की रणनीति बनाई गई. विधायक दल की बैठक को लेकर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि विपक्ष के सवालों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे. वहीं बीजेपी वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने बैठक को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि माहौल हर्ष और उल्लास से भरा रहा. उन्होंने बताया कि इस मौके पर भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर केक काटा गया. विपक्ष के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने (विपक्ष ने) भी बहुत से कारनामे किए हैं. हम जवाब देने के लिए बैठे हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी और यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. शीतकालीन सत्र में कुल चार बैठकें होंगी.

शाह 3 दिनों के लिए आ रहे छत्तीसगढ़

सरेंडर कर चुके नक्सलियों से करेंगे चर्चा

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे. 14 से 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान शाह राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे. सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा नक्सल प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे. यह पहला मौका होगा, जब अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं.

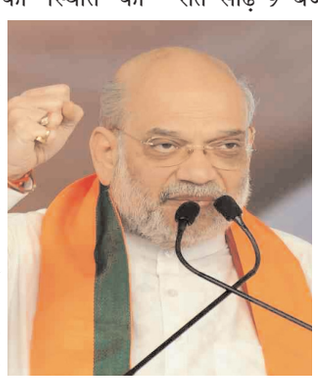

बता दें कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया था. इस दौरान सीएम ने बताया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के सफाए के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसकी लगातार सफलता मिल रही है.

जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम- मिनट टू मिनट जारी कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 14 दिसंबर को रात साढ़े 9 बजे रायपुर पहुंचेंगे और होटल मेफेयर रिसार्ट में रात्रि विश्राम करेंगे. 15 दिसंबर को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में आयोजित राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद ढाई बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे. सरेंडर करने वाले नक्सलियों से भी मुलाकात करेंगे. इसके अलावा नक्सल प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे. 16 दिसंबर को शाम 4 बजे बस्तर से रायपुर लौटेंगे. इसके बाद 6 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा नेताओं को फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनाने की मास्टरी

रायपुर। भाजपा सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर तंज कसते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच से उतरकर जनता के बीच जाते तब उन्हें पता चलता कि उनकी सरकार का सीआर कितना खराब है। भाजपा नेता फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनाने में मास्टरी किए हुए हैं। भाजपा कार्यालय में बैठकर फर्जी आंकड़े, झूठी कहानी गढ़कर रिपोर्ट कार्ड बनाकर जनता को भ्रमित करते हैं। सरकार का असली रिपोर्ट कार्ड तो जनता के पास में है और जनता यह बात मान चुकी है कि यह सरकार एक साल में अलोकप्रिय हो चुकी है जनता की नजरों से उतर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 साल के भीतर प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकता फैला है, हर वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित और भयभीत हैं और सरकार में बैठे लोग जनता की आवाज को सुन नहीं रहे। भाजपा सरकार से नक्सली और अपराधी दोनों नियंत्रित नहीं हो पा रही है। प्रदेश में चाकू बाजी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, गैंगरेप, गोलीबारी की घटना हो रही है, कोई ऐसा शहर, ब्लॉक नहीं बचा है जहां रोज आपराधिक घटनाएं न हो रहा हो। सरकार के खिलाफ किसान, व्यापारी, युवा, छात्र, शासकीय कर्मचारी सभी आंदोलन कर चुके हैं।

उच्च शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग का निर्णय

रायपुर। भाजपा सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग से भरने के आदेश पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी के एक लाख पदों को स्थानीय युवाओं की भर्ती से पूरा करने का वादा कर चुनाव जीतने वाली भाजपा ने अब अपना असली रंग दिखा दिया है। जिस तरह से पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सरकार के 15 साल के कुशासन के दौरान सरकारी नौकरी में आउटसोर्सिंग करके छत्तीसगढ़ के युवाओं के सरकारी नौकरी में रोजगार के अवसर बेचे, उसी तर्ज पर अब एकबार फिर उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक के 1209 पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। साय सरकार का यह फरमान छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति विश्वासघात है। छत्तीसगढ़िया युवाओं से भाजपा सरकार को इतनी हिकारत क्यों है? अनियमित कर्मचारियों को 100 दिन में नियमित करने का वादा झूठा निकला अब आउटसोंस करके स्थानीय युवाओं का हक छीन रही है। बीते एक साल से नई सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे युवाओं को सरकार ने धोखा दिया है, प्रदेश के युवा ढूंढ रहे हैं कहाँ है स्थानीय भर्ती? कहां है वेकेंसी?

जनता भाजपा के झूठी कहानियां सुनना नहीं चाहती - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आये थे, साय सरकार की एक साल की उपलब्धि को गिनाने लेकिन जेपी नड्डा को सुनने छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आयी। पूरी मशीनरी, पूरी ताकत को झोकने के बाद, सत्ता के अंधाधुंध पैसे का दुरुपयोग करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतने लोगों को नहीं जुटा पायी की जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिये जो पंडाल बनाया गया था उसकी कुर्सियां भर सके। अपने मुंह मिया मिट्ठू बनने के लिये सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को खर्चा करके कार्यक्रम किया गया लेकिन जनता ने उससे दूरी बना लिया था। कलेक्टर, एसपी को भीड़ लाने टार्गेट दिया गया, वे भी लोगों को नहीं जुटा पाये। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह सरकार की अलोकप्रियता को बताता है कि सरकारी कार्यक्रम फेल हो गया। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था। दरअसल भारतीय जनता पाटी एक साल में छत्तीसगढ़ में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती घटनाओं के कारण छत्तीसगढ़ की जनता आहत है। पिछले एक साल से वादाखिलाफी की गयी।

भाजपा युवा नेता दीपक यंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित

रायपुर। भाजपा के युवा नेता उज्ज्वल दीपक को राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नेतृत्व क्षमता और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए ऋषिहुड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित यंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कार्यक्रम ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत द्वारा दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु और प्रसिद्ध उद्योगपति श्री अजय पीरामल जी द्वारा यह अवार्ड उज्ज्वल दीपक को प्रदान किया गया। यंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार का आभारी हूँ। मुझे प्रसन्नता है की मेरे द्वारा किए जा रहे राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को विश्वविद्यालय ने इस अवार्ड के माध्यम से प्रोत्साहित करते हुए मुझे देश की राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की है। मैं इस अवार्ड को छत्तीसगढ़ प्रदेश के अपने युवा अभ्यर्थियों को समर्पित करना चाहता हूँ.

पीएम आवास स्वीकृति के बाद भी लाभान्वित नहीं हो रहे

रायपुर। सर्वे के 13 वर्षों बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृति होने के बाद भी अनेकों लाभार्थी इसका लाभ उठा पाने से वंचित होने जा रहे हैं क्योंकि इस 13 वर्षों के अंतराल में अपने परिवार के आवास की? भयावह समस्या को देखते हुये वे जुगाड़ कर आवास निर्माण कर चुके हैं और अब स्वीकृत आवास निर्माण करने उनके पास अतिरिक्त भूमि नहीं है और निर्मित आवास पर इस स्वीकृत राशि से प्रथम तल निर्माण की अनुमति नहीं है । ऐसे लाभार्थियों की समस्या की ओर ध्यानाकृष्ट कराते हुये केन्द्र व प्रदेश के मंत्रियों को ज्ञापन भेज इन्हें राहत देने नीतिगत निर्णय लेने का आग्रह किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने किया है । केन्द्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर व राज्य मंत्री तोखन लाल साहू सहित छग के आवास मंत्री ओ पी चौधरी को ज्ञापन प्रेषित कर इसकी प्रति विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर रमन सिंह व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भी प्रेषित किया गया है । क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी इसकी प्रति भेज केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का आग्रह किया गया है। इन सभी को मेल से भेजे गये ज्ञापन में या तो इनके द्वारा किये गये आवास का सत्यापन करवा निर्धारित राशि दिये जाने या फिर फर्स्ट फ्लोर निर्माण की स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया है। साथ ही इस संबंध में नीतिगत निर्णय होने तक आबंटन निरस्ती प्रक्रिया को शुरू न करने का अनुरोध भी किया गया है।

1 साल छत्तीसगढ़ बदहाल के पोस्टर कांग्रेस ने किया जारी

प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा जिलों में 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया

रायपुर। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 1 घंटे का सरकार की बदहाली को लेकर पोस्टर प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत शहर के मुख्य चौक-चौराहों पर कांग्रेसजन भाजपा सरकार के विभिन्न विफलताओं बलौदाबाजार अग्निकांड, लोहारीडीह हत्याकांड, बलरामपुर पुलिस अभिरक्षा में हुयी मौत, आदिवासी फर्जी मुठभेड़, हसदेव जंगल कटाई, महिलाओं के साथ हो रही अनाचार, प्रदेश में बदहाल कानून-व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों का पोस्टर बनाकर मौन-प्रदर्शन करते हुए आम जनता का ध्यान आकृष्ट कराया गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। साय सरकार की उपलब्धि को के नाम पर पिछली सरकार की योजनायें बंद करना मात्र है। साय सरकार ने जनता के हित में चलाई जाने वाली योजनओं को

दुर्भावनापूर्ण बंद किया। राजीव मितान योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, रीपा, मुख्यमंत्री कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी, महिला समूहों की ऋण माफी, सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि, सीएम छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि, कोदो कुटकी रागी खरीदी, नरवा-गरवा-घुरवा बारी, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, मुख्यमंत्री महतारी दुलार, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन, धरसा विकास, शहरी गरीबों को पट्टा एवं आवास, छत्तीसगढ़िया ओलिंपिक, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को बंद किया। यह सरकार दुर्भावना वाली सरकार है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कही नहीं दिख रही। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी। राजधानी में 6 बार गोली बारी हो गयी। गौ तस्करी की घटनाएं शुरू हो गयी। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गयी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी। नक्सली घटनायें बढ़ गयी, सरकार ने 1 साल में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है।

निजीकरण के विरोध में देश भर में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण विरोधी दिवस मनाकर विरोध दर्ज किया

रायपुर। नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर में समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने आज निजीकरण विरोधी दिवस मनाया और समस्त जनपदों , परियोजनाओं में सभा की। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमेन शैलेन्द्र दुबे और सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव ने उप्र पावर कार्पोरेशन प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है और भय का वातावरण बनाकर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना रहा है । उन्होंने चेतावनी दी कि प्रबंधन बिडिंग प्रक्रिया शुरू करने के पहले आर एफ पी डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जारी करे तो निजीकरण के खतरों का अपने आप खुलासा हो जाएगा। आज उप्र और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्व्यापी 'निजीकरण विरोधी दिवस' मनाया गया और देशभर में समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध सभाएं की गई। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओ ई ई ई) ने चेतावनी दी है कि उप्र में निजीकरण के बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी होते ही देश भर में लाखों बिजली कर्मी सड़क पर उतरने को विवश होंगे। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का बिजली विभाग निजी कंपनी को सौंपने की कोई भी कोशिश की गई तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी और देशभर में बिजली कर्मी सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने निजीकरण को बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। चंडीगढ़ की बिजली की 22000 करोड़ रु की परिसंपत्तियों को निजी कंपनी को मात्र 871 करोड़ रु में दिया जा रहा है। उप्र और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में मुम्बई, कोलकाता,चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, नागपुर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, चंडीगढ़, पटियाला, रांची, आदि स्थानों पर बड़े प्रदर्शन हुए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.